Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 337
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

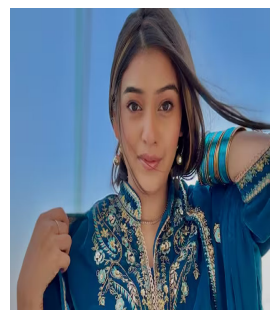

3 पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट ...

4 धुरंधर को टारगेट करने वालों को पहले ...

7 रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भारतीय...

संक्षिप्त न्यूज

जब मतदान हो चुका था तो चोरी कैसे हो सकती है? अमित शाह को डीके शिवकुमार का जवाब

बैंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू के समय में 'वोट चोरी' के दावे का खंडन करते हुए कहा कि शाह को इस विषय की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उस समय मतपत्र होते थे, इसलिए वोटों की चोरी या हेराफेरी जैसी कोई घटना संभव ही नहीं थी। शिवकुमार ने कहा कि अमित शाह को 'वोट चोरी' की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उस समय मतपत्र होते थे, और अब नहीं हैं। जब मतपत्र थे, तब 'चोरी' कैसे हो सकती है? यह निराधार है।

इससे पहले आज, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि कल अमित शाह जी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं। यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी है कि वे मैदान में आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला।

बुधवार को लोकसभा में तनाव तब बढ़ गया जब अमित शाह और राहुल गांधी के बीच 'वोट चोरी' के आरोपों पर तीखी बहस हुई। गांधी ने शाह को बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावे भी शामिल थे। शाह ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी।

पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत कर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।

दोनों नेताओं ने माना कि दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच तेज़ी से मजबूत होते संबंध वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बातचीत का मुख्य फोकस रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहराई देना रहा।

मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करते हुए द्विपक्षीय सहयोग में हो रही निरंतर मजबूती पर संतोष जताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार बढ़ाने के लिए गति बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही दोनों ने यह भी माना कि आने वाले समय में दोनों देशों को नई तकनीकों, रक्षा और सुरक्षा में आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।

महत्वपूर्ण तकनीक और रक्षा सहयोग

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कॉम्पैक्ट कार्यक्रम पर भी चर्चा की। यह कार्यक्रम 21वीं सदी के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। मोदी और ट्रंप ने महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने माना कि इन क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के हित में है।

वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को लेकर भी विचार साझा किए। बातचीत में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सहयोगात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने माना कि कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर मिलकर काम करने से प्रभावी समाधान निकल सकता है। मोदी और ट्रंप ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई।

रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को संतुलित और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों नेताओं ने संपर्क बनाए रखने और आगे भी नियमित बातचीत करते रहने का निर्णय लिया। उनके अनुसार, निरंतर संवाद से द्विपक्षीय संबंध और बेहतर होंगे और दोनों देशों के साझा हितों को मजबूती मिलेगी।

बंगाल मेरे खून और दिल में बसा है, बोले राज्यपाल सीवी बोस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को बंगाल को स्वप्नभूमि बताते हुए कहा कि वे हर तरह से बंगाली बनना चाहेंगे। बंगाल को वोट देने की अपनी इच्छा के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल बोस ने कहा कि बंगाल मेरी सपनों की भूमि है। बंगाल मेरे खून और दिल में बसा हुआ है। मैं हर तरह से बंगाली बनना चाहूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरा वोट बंगाल को ही जाएगा। मैंने इसके लिए आवेदन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे वोट मिल जाएगा।

राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हितधारकों को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर भी बात की। यह पूरे देश, विशेष रूप से बंगाल के लिए दिवाली मनाने का अवसर है, जो भारत की सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रतीक है और जिसे यूनेस्को ने अमूर्त विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। इससे नई पीढ़ी को लाभ होगा क्योंकि भारत का भविष्य उसके अतीत में निहित है। इस बीच, केरल के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की समय सीमा बढ़ा दी।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात के लिए गणना अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, और मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।

सरकारी संस्थानों को खत्म करने की साजिश हो रही', राहुल बोले- ये भारत के भविष्य के लिए खतरनाक

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर सरकारी संस्थानों को कमजोर करने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह साजिश गहरी है और भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति सरकारी कंपनियों को पहले बदहाल करना, फिर घाटे का हवाला देकर उन्हें अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपना है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी नीतियां देश के विकास, रोजगार और जनता के हितों के खिलाफ हैं।

राहुल गांधी ने संसद कार्यालय में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) के कर्मचारियों से मुलाकात का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला और वे कर्ज तथा उधार पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि कभी लाभ में रहने वाली बीआईबीसीओएल को 2017 के बाद 'सोच-समझकर' घाटे में धकेला गया। राहुल के मुताबिक, इसके जरिए टीकों के सरकारी अनुबंध निजी कंपनियों को सौंपने का रास्ता साफ किया गया ताकि वे महंगे दामों पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफा कमा सकें।

राहुल ने आरोप लगाया कि जेवर एयरपोर्ट के कारण बुलंदशहर स्थित बीआईबीसीओएल की जमीन की कीमत बढ़ गई है। इसी वजह से इसे बंद कर इसके बहुमूल्य संसाधन मित्रों को बेहद कम कीमत पर देने की तैयारी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्मचारियों की स्थिति सरकार को बताई गई है और वेतन तथा एरियर जल्द देने का आश्वासन मिला है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी एसआईआर की समयसीमा, जारी हुआ नया शेड्यूल

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीखों में संशोधन कर रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मतदाता सूची की एसआईआर अनुसूची में संशोधन किया गया है। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के बाद चुनाव निकाय ने एसआईआर के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात को अब अपनी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 14 दिसंबर, 2025 (रविवार) थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और नई जमा

करने की तिथि 23 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई है, जो पहले की 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) की समय सीमा का स्थान लेगी। उत्तर प्रदेश को अब अपनी एसआईआर रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2025 (बुधवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) थी।

भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) का दूसरा चरण चला रहा है। SIR का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सितंबर में पूरा हो गया था। यह प्रक्रिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करती है।

इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं, जहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की गई है। इसे 'विशेष संशोधन' कहा जा रहा है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम एपिं 2002 और 2004 के बीच हुआ था, और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए अंतिम SIR के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। SIR का मुख्य उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।

गाय को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की उठी मांग, राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों में सामान्य कामकाज देखने को मिला है। हालांकि, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई है। राज्यसभा में जहां जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में वार-पलटवार हुआ। वहीं, लोकसभा में निशिकांत दुबे की मांग पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा ने उन विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल बृहस्पतिवार को बढ़ा दिया, जिनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। वहीं, लोकसभा में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उस समय एक विचित्र स्थिति से गुजरना पड़ा जब अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते समय उन्हें जेब में हाथ डाले रखने पर नसीहत दी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में 'नेशनल हेराल्ड' मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध किया। सदन में हंगामे के बाद पीठासीन सभापति

दिलीप सैकिया ने कार्यवाही शाम चार बजकर सात मिनट पर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश में देसी गायों की नस्लों को संरक्षण देना चाहिए और गाय को 'राष्ट्रमाता' या 'राजमाता' का दर्जा दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के उज्ज्वल रमण सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, "गाय राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है। देश में देसी गायों की आबादी तेजी से घट रही है। उनकी गरिमा, सम्मान और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।"

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को बहाना बनाना बंद कर, ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सदन में कांग्रेस के सचेतक ने कहा, "दिल्ली में लोग वायु प्रदूषण से इतने परेशान हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई की बात कही। ठाकुर ने प्रश्नकाल में हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के दौरान कहा, "देशभर में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है। सदन में क्या ई-सिगरेट पीने की अनुमति है?" जब लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 'नहीं' में जवाब दिया तो ठाकुर ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य पिछले कई दिन से सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं।" हालांकि, भाजपा सांसद ने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया।

जेपी नड्डा द्वारा वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि क्या चर्चा का विषय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है या फिर चर्चा का मुख्य विषय जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नड्डा के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया और नेहरू पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस वंदे मातरम को लेकर है

ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा वार

पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में हाल ही में हुए गीता पाठ कार्यक्रम में दो ठेलेवालों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि राज्य में इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नदिया जिले के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। उन्होंने ठेले बेचने वालों को पीटा... हमने कल रात सभी को गिरफ्तार कर लिया। बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन की संस्कृति फैलाने का आरोप लगाया। भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि मैं सांप्रदायिक विभाजन में विश्वास नहीं करती। मैं सभी धर्मों के साथ चलना चाहती हूं। गीता पाठ के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करने की क्या आवश्यकता है? जो लोग ईश्वर से प्रार्थना

करते हैं या अल्लाह से आशीर्वाद मांगते हैं, वे अपने हृदय में ऐसा करते हैं।

धार्मिक ग्रंथों का राजनीतिक लामबंदी के लिए इस्तेमाल करने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो लगातार 'गीता, गीता' जपते रहते हैं - श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में क्या कहा था? धर्म का अर्थ है पालन करना, विभाजन करना नहीं। वे पश्चिम बंगाल को नष्ट करना चाहते हैं। वे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं और लोगों को बंगाली बोलने से रोकना चाहते हैं। हम सभी गीता पढ़ते और सुनाते हैं। इसके लिए सभा आयोजित करने की क्या आवश्यकता है?

कोलकाता पुलिस ने बुधवार रात को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 7 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित 'पांच लोक्खो कोंठ गीता पाठ' के दौरान दो खाद्य विक्रेताओं पर हमला किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज दो शिकायतों के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गईं।

संसद में ई-सिगरेट पर बवाल! अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर लगाया आरोप, स्पीकर ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। गुरुवार को लोकसभा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य सदन के अंदर ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह न केवल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अनुमति कभी नहीं दी गई थी और कहा कि यदि लिखित शिकायत दर्ज की जाती है और आरोप की पुष्टि होती है तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे।

यह मामला प्रश्नकाल के दौरान तब उठा जब ठाकुर ने उठकर सदन के नियमों के बार-बार उल्लंघन का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरा सदन इस मुद्दे से अवगत हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महोदय, मेरा सदन से एक प्रश्न है। महोदय, पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है? अध्यक्ष ने उत्तर दिया, 'नहीं, कोई भी इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।'

ठाकुर ने कहा कि महोदय, क्या आपने इसकी जाँच की है? टीएमसी के कुछ सांसद इसका सेवन कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँगों को स्वीकार करते हुए, बिरला ने दोहराया कि आचार संहिता सभी सांसदों पर समान रूप से लागू होती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी औपचारिक शिकायत की गंभीरता से जाँच की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का भी आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी सांसदों से संविधान के नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध करता हूँ। यदि कोई सांसद इस तरह का कोई मुद्दा लेकर मेरे पास आता है, तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूँगा।

जयराम रमेश का दावा, पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने नहीं पढ़ी राष्ट्रगान पर लिखी महत्वपूर्ण किताबें

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को लोकसभा में चल रही वंदे मातरम बहस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनके साथियों ने राष्ट्रगान की सच्ची भावना पर लिखी गई दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें भी नहीं पढ़ी हैं। ये पुस्तकें रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखित 'सॉन्ग ऑफ इंडियाः ए स्टडी ऑफ नेशनल एंथम' और सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा लिखित 'वंदे मातरमः द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग' हैं।

जयराम रमेश ने तीखे शब्दों में कहा कि ये पुस्तकें दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं से यह उम्मीद करना अतिशयोक्ति है, जबकि वे जनता के सामने अपने झूठ के लिए बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक वंदे मातरम पर बहस हुई। कुछ भाषणों में राष्ट्रगान का ज़िक्र भी हुआ... यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और उनके पूरे दल ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर लिखी गई दो प्रामाणिक और महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं - जो भारत के दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा सही मायने में लिखी गई हैं। यह उम्मीद करना अतिशयोक्ति है कि झूठ के लिए बुरी तरह लताड़ने और बेनकाब होने के बाद भी वे ऐसा करेंगे।

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना की भूमिका पर प्रकाश डाला, वहीं भाजपा और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम वह शक्ति है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिकल्पित सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। वंदे मातरम ने भारत में हजारों वर्षों से गहराई से निहित एक विचार को पुनर्जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक सर्वव्यापी मंत्र है जो स्वतंत्रता, त्याग, शक्ति, पवित्रता, समर्पण और लचीलेपन को प्रेरित करता है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- अमित शाह ने लोकसभा में उनकी दलीलों को 'धोया'

नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का बचाव किया और विपक्ष पर निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। दुबे की यह टिप्पणी शाह द्वारा चुनावी प्रक्रिया से लेकर शासन में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका तक के मुद्दों पर विपक्ष के नेता के भाषण का विस्तृत खंडन करने के एक दिन बाद आई है।

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने कहा कि अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। उन्होंने दावा किया, 'भारत के विभाजन के बाद, शहीदों की चिता पर, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का आनंद लिया, और सत्ता का आनंद लेने वाले परिवार के लोग देश, दुनिया और शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते।' उन्होंने कांग्रेस के भीतर वंशवादी राजनीति की भाजपा की पुरानी आलोचना को दोहराया।

दुबे ने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में तैयारी और गहराई का अभाव था, जिसके चलते गृह मंत्री के लिए उनके तर्कों का बिंदुवार खंडन करना आसान हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के आए थे; उनके भाषण के तीन मुख्य बिंदुओं को गृह मंत्री ने बड़ी कुशलता से 'वॉशिंग मशीन' में धो दिया, इसलिए न तो जनता राहुल गांधी के शब्दों को गंभीरता से लेती है और न ही देश उन्हें गंभीरता से लेता है।

प्राडा, लिडकॉम और लिडकार ने कोल्हापुरी चप्पलों के ग्लोबल प्रमोशन के लिए MoU साइन किया

पारंपरिक कोल्हापुरी कारीगरी के लिए प्राडा का मॉडर्न सपोर्ट

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

मुंबई। ग्लोबल ब्रांड प्राडा, लिडकॉम (संत रोहिदास लेदर एंड लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) और लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) ने भारतीय पारंपरिक लेदर के लिए कोल्हापुरी चप्पलों की विरासत को दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए एक श्दळ साइन किया है। यह एग्रीमेंट इटली-इंडिया बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई में इटैलियन कॉन्सुलेट में साइन किया गया।

इन चप्पलों को सदियों से इस्तेमाल हो रहे पारंपरिक चप्पल बनाने के तरीकों और प्राडा के मॉडर्न और कंटेंपररी डिज़ाइन स्टाइल का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा है। पारंपरिक स्किल्स और मॉडर्न लग्ज़री फैशन की मदद से, पारंपरिक कोल्हापुरी कारीगरी को प्राडा से मॉडर्न सपोर्ट मिलेगा। ये खास चप्पलें फरवरी 2026 में 40 प्राडा सेल्स आउटलेट्स के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेंगी।

इस पहल को महाराष्ट्र सरकार से पूरा सपोर्ट मिला है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल से एक्टिव गाइडेंस मिली है। यह एग्रीमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और LIDCOM के प्रेसिडेंट डॉ. हर्षदीप कांबले के गाइडेंस और LIDCOM की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेरणा देशभ्रतार की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मुमकिन हुआ है।

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि इस एग्रीमेंट से भारत में कई कारीगरों, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा। यह खास कलेक्शन भारतीय कारीगरों की कला को एक नई दिशा देगा और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान को और मजबूत करेगा।

लिडकॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेरणा देशभ्रतार ने कहा कि पारंपरिक कला को बचाकर रखने वाले कारीगरों की पीढ़ियों को सम्मान देने और ग्लोबल लेवल पर उनके हुनर को सही पहचान दिलाने के लिए यह पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। चूंकि एक ग्लोबल ब्रांड सीधे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगरों के साथ काम कर रहा है, इसलिए उनके हुनर को पहचान मिलेगी और इन कारीगरों को उनकी कला का पूरा क्रेडिट मिलेगा।

लिडकर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. के. एम. वसुंधरा ने कहा, 'कोल्हापुरी चप्पलों की परंपरा महाराष्ट्र-कर्नाटक के चप्पल बनाने वालों का सदियों से जमा किया हुआ हुनर है। इस सहयोग से ट्रेनिंग, रोज़गार और ग्लोबल मौकों के दरवाज़े खुलेंगे।

प्राडा ग्रुप के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड लोरेंजो बर्टेली ने कहा, 'यह पार्टनरशिप कल्चरल एक्सचेंज की एक नई पहचान है। हम भारतीय कारीगरों की बेमिसाल कला को आज की दुनिया में उनकी सही जगह दिलाने के लिए कमिटेड हैं।

यह एग्रीमेंट चप्पलों के कलेक्शन के ज़रिए भारतीय कारीगरी के 'प्राडा मेड इन इंडिया- कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित' प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन, लागू करने और गाइडलाइंस की आउटलाइन देता है। ये चप्पलें महाराष्ट्र और कर्नाटक में पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलें बनाने वाले हुनरमंद कारीगरों की मदद से भारत में बनाई जाएंगी। इन चप्पलों को बनाने के पारंपरिक तरीकों को प्राडा के कंटेंपररी डिज़ाइन और प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल के साथ मिलाकर, यह कलेक्शन भारत की समृद्ध विरासत और मॉडर्न लग्ज़री फ़ैशन के एक्सप्रेशन के बीच एक नई बातचीत शुरू करेगा।

पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के चार ज़िलों (कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर) और कर्नाटक के चार ज़िलों (बेलगाम, बागलकोट, धारवाड़, बीजापुर) में बनती हैं। ये आठ ज़िले चार सबसे मशहूर और मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों का घर हैं। 2019 में, कोल्हापुरी चप्पलों को ज्योग्राफ़िकल इंडिकेशन (GI) टैग दिया गया, जिससे उनकी असली पहचान बनी रही और उनके सांस्कृतिक महत्व पर ज़ोर दिया गया।

पश्चिम रेलवे चलाएगी बांद्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की सुविधा तथा यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09604 बांद्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल (01 फेरे)

ट्रेन संख्या 09604 बांद्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा स्पेशल शुक्रवार, 12 दिसम्बर 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 18:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:40 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी।

यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में AC-2 टियर, AC-3 टियर, AC-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09604 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry .indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे ने मनाया सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस - 2025

जन-सुरक्षा, तत्परता एवं कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे सिविल डिफेन्स संगठन द्वारा सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस का आयोजन गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, महालक्ष्मी में किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा सिविल डिफेन्स ध्वज फहराया। उन्होंने उपस्थित रेल अधिकारियों, सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को संबोधित किया तथा स्वयंसेवकों को सामुदायिक क्षमता-निर्माण एवं संकट की स्थिति में लोगों की सहायता हेतु निरंतर योगदान देने का आवाहन किया।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत नौ टुकड़ियों की एक औपचारिक परेड से हुई, जिसमें एक सर्व-महिला टुकड़ी भी शामिल थी। इसके बाद सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों—जैसे हवाई हमले एवं बम विस्फोट—के दौरान अपनाई जाने वाली बचाव एवं राहत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। कोच के अंदर लगी आग को बुझाने की प्रक्रिया प्रदर्शित करने हेतु फायर-बॉल का उपयोग करते हुए एक विशेष अग्निशमन ड्रिल भी आयोजित की गई। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और ट्रेसपासिंग की रोकथाम के महत्व का संदेश देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सिविल डिफेन्स उपकरणों, साधनों एवं तैयारियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो पश्चिम रेलवे की मजबूत सिविल डिफेन्स क्षमताओं को प्रतिबिंबित करती है। अपने संबोधन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों की निष्ठा, समर्पण एवं सेवाभाव की सराहना की तथा उन्हें सामुदायिक क्षमता-निर्माण और आपातकालीन सहायता में निरंतर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक (जी) एवं नियंत्रक, सिविल डिफेन्स, श्री उज्ज्वल देव के मार्गदर्शन में किया गया।

पश्चिम रेलवे सिविल डिफेन्स की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा, लचीलापन एवं सामुदायिक सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करता है।

सिंगापुर, जर्मनी, एस्टोनिया के स्टूडेंट्स स्टडी विज़िट के लिए नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई शहर एक मॉडर्न शहर के तौर पर जाना जाता है और कई देसी-विदेशी स्कॉलर और स्टूडेंट्स नवी मुंबई में नए प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए नवी मुंबई शहर आते हैं। इसी तरह, आज सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, कामों और उनकी खासियतों के बारे में जाना।

सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने आज रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़रिए नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर म्युनिसिपल सेक्रेटरी श्रीम. चित्रा बाविस्कर ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर म्युनिसिपल एडवाइजरी ग्रुप ने संबंधित स्टडी ग्रुप को म्युनिसिपल सेक्टर में चल रहे खास

प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी दी। इनमें वॉटर सप्लाई मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग, रोज़ाना की सफाई शामिल हैं। प्रदूषण रोकने के उपाय, समय-समय पर सफाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव, नशा छुड़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, हेल्थ केयर सुविधाएं, कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ का सामान, पेवर ब्लॉक, प्लास्टिक-फ्री शहर के लिए किए गए उपाय, टेक्सटाइल वेस्ट पर रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट, साथ ही सूखे कचरे से बिजली और गीले कचरे से बायोगैस बनाने जैसे संभावित प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया और जानकारी दी गई।

इसी तरह, कल, 10 दिसंबर को, जर्मनी और एस्टोनिया, दो देशों के 40 से ज़्यादा स्कूली छात्रों ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के ज़रिए नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया और शहर की खासियतों के बारे में जाना।

इन तीन देशों के कॉलेज और स्कूली छात्रों के स्टडी ग्रुप ने भारत के शहरों में नवी मुंबई की खासियत को बताया और अपनी प्रतिक्रिया दी कि वे कई अलग-अलग चीज़ों का अनुभव कर पाए।

महाप्रबंधक, मध्य रेल द्वारा 'दिव्यांगजनों के लिए खास दिवस' के अवसर पर दिव्यांगजन रेलवे कर्मचारियों का सम्मान

महाप्रबंधक ने दिव्यांगजन कर्मचारियों और उनके दिव्यांगजन आश्रितों को विशेष दिव्यांग-अनुकूल उपकरण भेंट किए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने मध्य रेल कर्मचारी लाभ कोष (सीएसबीएफ) के तत्वावधान में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2025 को सीएसएमटी सभागार में आयोजित 'दिव्यांगजनों के लिए खास दिवस' के उपलक्ष्य में दिव्यांगजन रेलवे कर्मचारियों को आदर्श पुरस्कार प्रदान किए।

स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र सहित ये पुरस्कार 16 दिव्यांगजनों को उनकी (विकलांगता) दिव्यांगता के बावजूद उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने और दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए। मुंबई मंडल के 9 दिव्यांगजनों को महाप्रबंधक द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि अन्य मंडलों के 7 दिव्यांगजनों को उनके मंडल रेल प्रबंधकों द्वारा महाप्रबंधक की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

इस व्यवस्था से दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को मुंबई तक की लंबी यात्रा की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

समारोह के मुख्य अतिथि और महाप्रबंधक गुप्ता ने तीन दिव्यांगजन रेलवे कर्मचारियों को दिव्यांग-अनुकूल उपकरण भेंट किए, जिनमें से दो कर्मचारियों को लैपटॉप (विशेष उपयोगकर्ता-अनुकूल सॉफ़्टवेयर के साथ) और एक कर्मचारी को लार्ज मैगनीफ़इंग ग्लास फ़्लैश लाइट के साथ प्रदान किया गया।

महाप्रबंधक ने रेलवे कर्मचारी के दिव्यांगजन आश्रित को बैसाखी का एक जोड़ा भी भेंट किया।

महाप्रबंधक ने इस अवसर पर प्रेरणादायक भाषण दिया। गौतम बुद्ध एवं स्टीफन कोवे के शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। दिव्यांगजनों ने यह विजय पहले ही प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज वे अन्य सामान्य व्यक्ति के बराबर एक मंच पर खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य रेल, दिव्यांगजनों के साथ सदा खड़ा रहेगा और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा, जिसमें कार्यस्थल पर विशेष सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। पी पी पांडे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं अध्यक्ष, सीएसबीएफ ने गणमान्य व्यक्तियों का शुभ सूचक पौधा दे कर स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें दिव्यांगजन कलाकारों की प्रस्तुतियां भी शामिल थीं।

कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोत्साहन भरे शब्दों और मध्य रेल द्वारा मुख्यालय, सभी 5 मंडलों, निर्माण संगठन और कारखानों में कार्यरत 1240 दिव्यांगजन कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी पहलों को जारी रखने की नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

इस कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक श्री प्रतीक गोस्वामी, अन्य प्रधान विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, मुंबई मंडल हिरेश मीना, मध्य रेल के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मध्य रेल द्वारा मुंबई और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन सेवाएं

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ट्रेन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए, मध्य रेल मुंबई और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन सेवाएं चलाएगा।

विवरण इस प्रकार हैः

हावड़ा-सीएसएमटी-हावड़ा - 2 सेवाएं

ट्रेन संख्या 02870 विशेष ट्रेन गुरुवार, दिनांक 11.12.2025 को दोपहर 13:55 बजे हावड़ा से प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को रात 23:45 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 02869 विशेष ट्रेन शनिवार, दिनांक 13.12.2025 को सुबह 11:05 बजे सीएसएमटी से प्रस्थान करेगी और रविवार को रात 20:55 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

ठहरराव : कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा राउरकेला, टाटानगर और खड़गपुर।

संरचनाः 2 एसी 2-टियर, 5 एसी 3-टियर, 2 एसी 3-टियर इकोनॉमी, 6 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड्स ब्रेक वैन और 1 जनरेटर/सामान वैन।

आरक्षणः

ट्रेन संख्या 02869 के लिए बुकिंग दिनांक 12.12.2025 से सभी पीआरएस वेंद्रों और ध्ंण्ऊण टा`बासाइट (www.irctc.co.in) पर शुरू हो जाएगी।

इन विशेष ट्रेनों के ठहराव एवं समय की विस्तृत जानकार के लिए, कृपया www.enquiry .indianrail.gov.in पर जाएं या ऊुं ऐप डाउनलोड करें। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें।

पश्चिम रेलवे
इलेक्ट्रिकल पावर कार्य

Sr.DEE/P/BCT टेंडर नोटिस नंबर EL-81-7-919-WA-22 (R-1) तारीख 08.12.2025 आमंत्रित करता है। **काम और स्थानः मुंबई सेंट्रल (मुख्य)-** बोम्बारसी- बोम्बारसी में हेरिटेज टाइप छत, ट्रस की मरम्मत सहित अंदरूनी और बाहरी रिनोवेशन के संबंध में इलेक्ट्रिकल पावर का काम। **काम की अनुमानित लागतः** 15,00,000/- **ईएमडीः** 30,000/- **जमा करने की तारीख और समयः** 02.01.2026 तक, 15:00 बजे। खोलने की तारीख और समयः 02.01.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0879

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में महिलाओं को प्राथमिकता देने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक होगी- स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

राज्य में जिला परिषद स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर उन स्कूलों में जहां लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक बैठक होगी, यह बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में कही।

सदस्य अरुण लाड द्वारा विधान परिषद में लक्षवेधी के माध्यम से उठाए गए इस मुद्दे पर हुई चर्चा में सदस्य चित्रा वाघ, जयंत असगांवकर, जे.एम. अभ्यंकर और विक्रम काले ने भाग लिया।

राज्य मंत्री भोयर ने कहा कि मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में महिलाओं के लिए कोई अलग से प्राथमिकता नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारी, पति-पत्नी का एक साथ होना और उम्मीदवार की पसंद जैसे कारक लागू होते हैं। भविष्य में, लड़कियों की संख्या के अनुसार महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में POCSO समितियां, युवा समूह, शिकायत निवारण प्रणाली और अन्य उपाय लागू किए जा रहे हैं। जिन स्कूलों में महिला काउंसलर या महिला शिक्षकों की कमी है, वहां संबंधित विभाग से सलाह करके महिला काउंसलर की व्यवस्था करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

राज्य मंत्री भोयर ने कहा कि 2008 के बाद 100 प्रतिशत अनुदान पर आए स्कूलों को गैर-वेतन अनुदान प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग के साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही, 2008 से पहले के स्कूलों को समय पर गैर-वेतन अनुदान प्रदान करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, उन्होंने इस दिलचस्प सवाल के जवाब में कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल और सीएम श्री स्कूल पहलों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, जिला नियोजन समिति के माध्यम से बड़ी मात्रा में फंड उपलब्ध कराया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे रेलवे बांद्रा टर्मिनस ⇄ दुर्गापुरा के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगी

ट्रेन संख्या	प्रारम्भिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तारीख	प्रस्थान	आगमन
09604	बांद्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा	12.12.2025	18:20 hrs (शुक्र)	14:40 hrs (अगले दिन)
हाल्टः बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशन।				
संरचनाः एसी - 2 टियर, एसी - 3 टियर, एसी - 3 टियर इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।				

टाइमिंग, स्टॉप और कंपोजिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 09604 के लिए बुकिंग सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर खुली है। यह ट्रेन स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
Like us on: facebook.com/WesternRly
Follow us on: X.com/WesternRly
Follow us on: Instagram/WesternRly

कृपया सभी रिज़र्व टिकटों के लिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ रखें।

पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 1209.08 करोड़ रुपये के कामों को मंज़ूरी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे शहर के लिए एक 'अग्नि निवारण योजना' तैयार की जानी चाहिए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र के शहरी विकास केंद्र के 27 गांवों में सीवेज ट्रीटमेंट योजनाओं के 1209.8 करोड़ रुपये के कामों को संशोधित प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई। इन कामों से संबंधित गांवों की 39 लाख 42 हज़ार आबादी को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि अथॉरिटी को फायर सर्विस चार्ज से जमा किए गए फंड का इस्तेमाल करने के लिए पुणे शहर के लिए एक 'अग्नि निवारण उपाय योजना' तैयार करनी चाहिए।

पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 13वीं बैठक विधान भवन के मंत्री परिषद हॉल में हुई। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फायर सर्विस चार्ज के लिए अथॉरिटी के पास बचे 300 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल पुणे महानगर में अग्नि निवारण योजना के अनुसार विभिन्न उपायों के लिए किया जाना चाहिए। पुणे महानगर से गुज़रने वाली नदियों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और नदियों में प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नदियों में प्रदूषित पानी न बहे।

नवाले ब्रिज पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, नेशनल हाईवे नंबर 48 और नेशनल हाईवे नंबर 548 DD की सर्विस सड़कों पर काम शुरू किया जाना चाहिए। नवाले ब्रिज के पास सर्विस सड़कें बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए, संबंधित एजेंसियों को तालमेल बिठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्लॉट डेवलपमेंट की संभावना की जांच की जानी चाहिए और पुणे ज़िला परिषद के अथॉरिटी के तहत आने वाले फैसिलिटी प्लॉट को ज़िला परिषद को देने के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पुणे शहर में मान-हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन 3 का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मेट्रो लाइन को लक्ष्य के अनुसार यात्रियों के लिए सेवा में लाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंस) ओपी गुप्ता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (शहरी विकास) असीम कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। पुणे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर योगेश म्हसे ने मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन दिया। डिविजनल कमिश्नर चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर नवल किशोर राम, जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी टेलीकॉन्फ्रेंस सिस्टम के ज़रिए मौजूद थे।

पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का विस्तार

पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में पुणे जिले की 9 तालुकों के 697 रेवेन्यू गांव शामिल हैं। इन गांवों का कुल क्षेत्रफल 5 हज़ार 383 वर्ग किलोमीटर है।

यवतमाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में कोई अनियमितता नहीं- सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल

नागपुर। सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने आज विधानसभा में कहा कि यवतमाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में भर्ती या वित्तीय अनियमितताएं नहीं हुई हैं। मंत्री पाटिल सदस्य अनिल मंगुलकर द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

सहकारिता मंत्री पाटिल ने कहा कि बैंक में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं देखी गई है। सदस्यों द्वारा बताई गई 516.65 करोड़ रुपये की राशि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, बल्कि 2019 में रिकॉर्ड की गलत व्याख्या के कारण पैदा हुई गलतफहमी है। चूंकि बैंक ने भर्ती के संबंध में नाबार्ड द्वारा निर्धारित चार अनिवार्य मानदंडों में से एक को छोड़कर बाकी सभी मानदंडों को पूरा किया था, इसलिए मांगी गई 267 पदों में से 50 प्रतिशत, यानी 133 पदों की अनुमति दी गई थी। बैंक में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कुछ शिकायतों के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल निलंबित है, और कोई 'फर्जी भर्ती' नहीं हुई है।

मंत्री पाटिल ने कहा कि हालांकि पिछले चार सालों में बैंक का NPA बढ़ा है, लेकिन प्रबंधन लागत अनुपात दो प्रतिशत से कम है। निदेशकों और अधिकारियों के यात्रा खर्च का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को एक जिला विशेष ऑडिटर नियुक्त किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस सीज़न में 19 लाख टन सोयाबीन की गारंटी मूल्य पर खरीद का लक्ष्य- विपणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विधान सभा में विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि इस सीज़न में नाफेड के माध्यम से 19 लाख टन सोयाबीन गारंटी मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कपास की खरीद के लिए सीसीआई केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

विधान सभा में विधायक संतोष दानवे ने नाफेड और सीसीआई के गारंटी मूल्य केंद्रों की स्थापना तथा कृषि उत्पादों व कपास को गारंटी मूल्य मिलने के संबंध में प्रश्न उपस्थित किया था। मंत्री रावल इस पर उत्तर दे रहे थे।

मंत्री रावल ने बताया कि पिछले वर्ष 11.25 लाख टन सोयाबीन की खरीद के बाद इस वर्ष 19 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संपूर्ण खरीद प्रक्रिया केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल और बायोमेट्रिक पद्धति से की जा रही है। मक्का की कमी न हो, इसलिए नाफेड और एनसीसीएफ को 120 करोड़ रुपये अग्रिम दिए गए हैं और राज्य में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

कपास खरीद के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पिछले सीज़न में 10,714 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी। इस वर्ष 168 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 156 कार्यरत हैं। केंद्रीय नियमों के अनुसार खरीद जारी है और किसानों को अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में हस्तक्षेप कर चर्चा की है।

वर्तमान में FAQ गुणवत्ता वाली कपास की खरीद 5,328 रुपये के गारंटी मूल्य पर की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50 अतिरिक्त केंद्र खोले गए हैं। राज्य में अनुमानित 80 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन में से लगभग 25 प्रतिशत की खरीद 'इंटरवेंशन स्कीम' के तहत की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार भावों में गिरावट को रोकना है, ऐसा मंत्री रावल ने कहा।

इस चर्चा में विजय वडेट्टीवार, कैलास पाटिल, बाबनराव लोनिकर और प्रकाश सोलंके ने भी भाग लिया।

'मुझे सीएम पर तरस आता है', उद्धव ठाकरे का फडणवीस पर निशाना; मंत्रियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नागपुर। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अपने 'भ्रष्ट' मंत्रिमंडल सहयोगियों को बचाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति में देरी पर सवाल उठाया।

उद्धव ठाकरे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फडणवीस पर निशाना साधा और उन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री पिछले कुछ वर्षों में 'बदल गए' हैं। नागपुर के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि किसी न किसी मंत्री का भ्रष्टाचार हर रोज उजागर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे ने कहा, 'उनके नेताओं के नोटों के बंडलों के साथ वीडियो सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री को एक 'सुरक्षात्मक पोर्टफोलियो' शुरू करना चाहिए और उसका प्रभार संभालना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'मुझे मुख्यमंत्री पर तरस आता है। आप (पहले) क्या थे और अब क्या बन गए हैं।' शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबदास दानवे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए, जिनमें कथित तौर पर शिंदे गुट की शिवसेना के एक विधायक को नकदी के बंडलों के बीच बैठे एक अन्य शख्स के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया है।

दानवे ने दावा किया कि नकदी सत्ताधारी दलों के विधायकों की थी, जबकि शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने वीडियो को मॉर्फ्ड और एआई-जनरेटेड बताकर खारिज कर दिया। एक दिन बाद किसान और मजदूर पार्टी की नेता चित्रलेखा पाटिल ने भी शिवसेना के एक मंत्री के बारे में इसी तरह का नकदी से जुड़ा दावा किया।

वहीं, ठाकरे ने सवाल उठाया कि विधानसभा और विधानपरिषद दोनों में विपक्ष के नेताओं (एलओपी) की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ महीने पहले, शिवसेना (यूबीटी) ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए पार्टी विधायक भास्कर जाधव का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने पूछा, 'अगर भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है, तो वह विधानसभा और विधानपरिषद में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है?'

अवैध छात्र परिवहन के संबंध में 1 से 31 जनवरी के बीच राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक

नागपुर। महाराष्ट्र के सभी जिलों में छात्रों को अवैध रूप से ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह पहल 1 से 31 जनवरी तक मुंबई सहित पूरे राज्य में लागू की जाएगी।

विधानसभा सदस्य डॉ. नितिन राउत ने एक ध्यान खींचने वाले सुझाव के माध्यम से, 2021 में नागपुर में हुई स्कूल वैन दुर्घटना के संदर्भ में एक सवाल उठाया, जब वह जवाब दे रहे थे।

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि संबंधित पुल पर चल रहे काम के कारण एक संकरी सड़क पर दो वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर और एक 13 साल के छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की जांच के परिणामस्वरूप छात्रों को अवैध रूप से ले जाने वाले 248 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

मंत्री सरनाइक ने कहा कि अगर कोई स्कूल बस या वैन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़क पर पाई जाती है, तो उसे जैमर लगाकर रोक दिया जाएगा। इसी तरह, अब कोई भी वाहन बिना फिटनेस के सड़क पर नहीं आना चाहिए। इसके लिए, AI तकनीक का उपयोग करके ऐसे वाहनों को सड़क पर आने से पहले ही रोकने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने 13+1 सुरक्षित स्कूल वैन मॉडल लागू किया है। इन वैन में सभी तरफ जाल लगाए गए हैं और इनमें CCTV और GPS जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं। साथ ही, कई स्कूलों ने पुरानी बसों को स्क्रैप करके नई सुरक्षित वैन खरीदना शुरू कर दिया है।

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि राज्य में ITMS सिस्टम, CCTV नेटवर्क और थ्री-डाइमेंशनल घाट मानचित्र बनाने का काम चल रहा है, और कहा कि अवैध यू-टर्न, लेन बदलने और ओवरलोडिंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ स्वचालित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

अक्टूबर में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवज़ा जनवरी में दिया जाएगा- राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद आबा पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नागपुर। राज्य में खरीफ और रबी मौसम के दौरान भारी बारिश से हुए कृषि नुकसान के लिए मुआवज़ा दिया जा रहा है। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने बताया कि अक्टूबर में राज्य में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवज़ा जनवरी से दिया जाएगा।

मंत्री मकरंद पाटिल सितंबर और नवंबर 2025 के बीच राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान के मुआवज़े के बारे में दिए गए एक अहम सुझाव पर बोल रहे थे। यह अहम सुझाव सदस्यों नीलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार ने दिया था।

मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य में, खासकर कोंकण में, अक्टूबर महीने में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए सहायता अभी शुरू नहीं हुई है और इसे दिसंबर के बाद बांटा जाएगा।

राहत और पुनर्वास मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की सहायता के अलावा, राज्य में छह महीने तक लगातार भारी बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों को अतिरिक्त सहायता दे रही है। सरकार ने NDRF के नियमों के अनुसार नियमित सहायता के अलावा रबी मौसम के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों की ज़मीन बारिश के कारण बह गई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर 47,000 रुपये की नियमित सहायता दी गई है, और इसके अलावा, राज्य सरकार ने MNREGA के तहत प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपये देने का भी फैसला किया है।

e-KYC के कारण सहायता वितरण में देरी से बचने के लिए, राज्य सरकार ने सहायता के लिए एग्री-स्टैक फार्मर ID को स्वीकार कर लिया है और 75 प्रतिशत से ज़्यादा किसानों के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

राज्य सरकार ने इस साल भारी बारिश के मुआवज़े के तौर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें से 14,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। श्री पाटिल ने इस मौके पर बताया कि खरीफ मौसम में 90 लाख किसानों को 7,156 करोड़ रुपये बांटे गए, जबकि रबी मौसम में 85.78 लाख किसानों को 6,864 करोड़ रुपये बांटे गए।

लाइसेंस वाले हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

नागपुर। विधानसभा में मुंबई में हॉकरों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सर्वे में लाइसेंस वाले हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट द्वारा बताए गए 20 व्यस्त जगहों पर हॉकरों को तुरंत वैकल्पिक जगह देने का निर्देश दिया।

विधानसभा में सदस्य अमीन पटेल ने मुंबई में हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में एक दिलचस्प सुझाव दिया। जिन हॉकरों के पास लाइसेंस हैं और जो सर्वे में रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरकार को हाई कोर्ट द्वारा हटाने का आदेश दिए गए 20 जगहों से हॉकरों को तुरंत वैकल्पिक जगह देनी चाहिए। लाइसेंस और सर्वे लिस्ट वालों के अलावा किसी और को हॉकिंग की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यह

निर्देश अध्यक्ष अंग नार्वेकर ने दिया।

इस दिलचस्प सुझाव पर जवाब देते हुए मंत्री डॉ. उदय सामंत ने कहा कि 2014 में किए गए सर्वे के अनुसार, 1,28,443 आवेदनों में से 99,435 आवेदन मिले थे और उनमें से 32,415 हॉकर योग्य थे। हॉकर समिति के चुनाव के बाद, कुछ स्ट्रीट वेंडरों ने कोर्ट में याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती रोक दी और मामला अभी भी पेंडिंग है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुंबई की 20 व्यस्त जगहों पर हॉकरों को बेचने से रोकने के निर्देश हैं। यह आम लोगों की रोज़ी-रोटी का मामला है। अगली सुनवाई में, सरकार सीनियर वकीलों के ज़रिए एक उचित पक्ष रखेगी। अगर हाई कोर्ट के आदेश के बिना दूसरी जगहों पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, तो नगर निगम से इसे तुरंत रोकने के लिए कहा जाएगा।

सभी फाइनेंशियल शर्तों को पूरा करने के बाद ही फंड दिए जाएंगे, राज्य सरकार का ध्यान इनकम के नए सोर्स बनाने पर- उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

नागपुर। राज्य सरकार खर्च पर कड़ा कंट्रोल, सख्त फाइनेंशियल अनुशासन, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और इनकम के नए सोर्स बनाने पर ध्यान दे रही है। उएऊ, एक्साइज ड्यूटी और माइनिंग विभागों के ज़रिए राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी है कि किसी भी फाइनेंशियल इंडेक्स को खराब होने दिए बिना राज्य का विकास तेज़ी से होता रहे। उपमुख्यमंत्री और वित्त और योजना मंत्री अजीत पवार ने बताया कि विंटर सेशन में सप्लीमेंट्री मांगों पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए, राज्य की फाइनेंशियल हालत को ध्यान में रखते हुए, सभी फाइनेंशियल नियमों का सख्ती से पालन करते हुए फंड बांटे गए।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि विंटर सेशन में कुल 75 हज़ार 286 करोड़ की सप्लीमेंट्री मांगें पेश की गई हैं, जिसमें से 38 हज़ार 600 करोड़ का फंड सिर्फ़ पब्लिक वेलफेयर स्कीमों और केंद्र के हिस्से के लिए है। इसमें

बाढ़ प्रभावित किसानों की राहत, बलिराजा बिजली सब्सिडी, सिंहस्थ कुंभ मेला, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजनाओं के लिए बढ़े हुए प्रावधान शामिल हैं। 10 हज़ार 600 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेंगे और राज्य पर कुल फाइनेंशियल बोझ 64 हज़ार 600 करोड़ है।

राज्य की कर्ज की स्थिति के बारे में, उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि राज्य वित्त आयोग द्वारा तय नियमों के अनुसार काम कर रहा है। राज्य सरकार हमेशा खर्च को कंट्रोल करके और साल के आखिर में फाइनेंशियल इंडेक्स का पालन करके फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखने में सफल रही है। इस साल भी, हालांकि सप्लीमेंट्री मांगों के ज़रिए प्रावधान किया गया है, सरकार एक नया रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स , एक्साइज ड्यूटी और माइनिंग विभाग के ज़रिए मिलने वाले रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, संसाधनों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके और फाइनेंशियल अनुशासन लागू करके, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संशोधित अनुमानों के अनुसार फाइनेंशियल घाटा कुल राज्य आय के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दोहराया कि राज्य का फाइनेंशियल अनुशासन कहीं भी खराब नहीं हुआ है।

सम्पादकीय

उड़ानें रद्द, महंगा किराया, जांच जारी, इंडिगो पर 10 फीसदी कटौती के बाद भी हालात काबू में क्यों नहीं?

विमानन कंपनी इंडिगो में उड़ान परिचालन का संकट अभी थमा नहीं है। अब तक हजारों उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा है। सरकार ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और साथ ही स्पष्ट किया है कि जांच निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में दस फीसद की कटौती कर दी है।

इस बात को तो सरकार ने भी माना है कि व्यवस्थागत खामियों की वजह से यह संकट पैदा हुआ है, लेकिन किस स्तर पर चूक हुई है, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। मगर सवाल है कि यह संकट खड़ा होने से पहले ही इसका समाधान तलाशने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई? इस अव्यवस्था का खमियाजा यात्रियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बुधवार को इस पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी गई। साथ ही कहा कि यह यात्रियों को हुई परेशानी और उत्पीड़न के अलावा देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का भी सवाल है।

हैरत की बात है कि जिन नए नियमों की वजह से इंडिगो में उड़ान परिचालन का संकट उपजा, उस आदेश को वापस लेने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। मसला सिर्फ यह नहीं है कि उड़ान रद्द होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई, बल्कि उन्हें दूसरी कंपनियों की उड़ान का सहारा लेने के लिए सामान्य से कई गुना अधिक किराये का भुगतान करना पड़ा। यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सवाल किया कि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में अन्य विमानन कंपनियां हालात का फायदा उठाकर यात्रियों से टिकटों के लिए भारी कीमत कैसे वसूल सकती हैं!

हालांकि, इस समस्या के उजागर होने के बाद सरकार ने फिलहाल दूरी के आधार पर हवाई किराये की सीमा तय कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि विमानन कंपनियों की यह मनमानी कोई एक बार की बात नहीं है। जब कभी उड़ान परिचालन का संकट पैदा होता है या फिर अत्यधिक व्यस्त समय हो, तो यात्रियों से मनमाना किराया वसूलना आम बात है। आखिर सरकार की ओर से इस पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी तौर पर व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है?

इसमें दो राय नहीं है कि पिछले करीब एक सप्ताह से उड़ान परिचालन में संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। देश भर में हर रोज हजारों लोग विमानों में सफर करते हैं और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में विमानन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है और घरेलू उड़ान क्षेत्र के लगभग पैंसठ फीसद हिस्से को नियंत्रित करती है।

सरकार का तर्क है कि इंडिगो की उड़ानों में कटौती से परिचालन को सामान्य करने में मदद मिलेगी। वहीं, नागर विमानन महानिदेशालय ने कंपनी पर निगरानी के लिए आठ सदस्यीय दल गठित किया है, जो रोजाना उड़ानों के परिचालन पर गहन नजर रखेगा। सवाल है कि इस तरह के उपाय अगर जरूरी थे, तो सरकार ने संकट पैदा होने के तत्काल बाद ये कदम क्यों नहीं उठाए? यात्रियों को केवल विमानन कंपनियों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया?

उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और विमानन कंपनियां जनहित को सर्वोपरि रखकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगी, ताकि भविष्य में इस तरह का संकट पैदा न हो।

धुरंधर को टारगेट करने वालों को पहले आईना देखना चाहिए

एक सीनियर फिल्मकार ने भारत की दुखती रग को दबाने वाले आतंकी वारदात पर वेबसीरीज बनायी तो उन पर पाकिस्तान के नजरिए को आगे बढ़ाने का आरोप लगा फिर भी लेफ्टविंग विद्वानों और मुख्यधारा के समीक्षकों ने उसकी जमकर तारीफ की। अब जब उसी आतंकी वारदात पर भारतीय या भारत के नजरिए से फिल्म बनाने का 'आरोप' लग रहा है वही वर्ग फिल्म की चीख-चीख कर निंदा कर रहा है।

मेरे ख्याल से धुरंधर की नींव उसी दिन पड़ गयी थी जिस दिन आईसी814 रिलीज हुई थी। आईसी814 में अजित डोभाल का रोल ऐसे एक्टर को दिया गया जो आमतौर पर मसखरों वाला रोल करते हैं। डोभाल के विरोधी का रोल उस आदमी को दिया गया जिसकी आम छवि बड़े एक्टर की है। नसीरुद्दीन साह और जसवंत सिंह दोनों राजस्थानी हैं और उनका लुक भी मिलता-जुलता है मगर शाह को सिंह की भूमिका नहीं दी गयी क्योंकि इससे डायरेक्टर की जसवंत सिंह को कमतर दिखाने की मंशा पूरी नहीं हो पाती।

पात्रों के चयन के मामले में अनुभव सिन्हा की चतुराई तक बात रहती तो कोई बात नहीं थी, मगर फिल्म का पूरा नरेटिव ही पूरी घटना को पाकिस्तानी सेना के नजरिए से दुनिया के सामने पेश करता है। उस फिल्म में अजित डोभाल को जिस तरह टारगेट किया गया वह बैड टेस्ट में था। अजित डोभाल को मोटा थुलथुल खबोच और मसखरा दिखाया गया है। असल लाइफ में डोभाल के

आलोचक भी उन्हें काबिल खुफिया अफसर मानते हैं, काबिल एनएसए भले न मानते हों।

190 व्यक्तियों की जान बचाने के लिए तीन आतंकियों की छोड़ना एक जटिल कठिन निर्णय है जो किसी के प्राण निचोड़ सकता है। मगर उस निर्णय को जिस तरह अनुभव सिन्हा ने अजित डोभाल को घेरने के लिए किया वह उनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। हिन्दी फिल्म जगत में किसी आतंकी घटना को पाकिस्तानी नजरिए से पेश करने का शायद यह पहला मामला रहा होगा।

धुरंधर का एक हिस्सा आईसी814 अपहरण मामले में अजित डोभाल का नजरिया पेश करता है। मेरे ख्याल से डोभाल वाला हिस्सा फिल्म में मौजूदा लंबाई से आधा या चौथाई होता तो बेहतर होता क्योंकि फिल्म का मुख्य प्लॉट कराची गैंगवार है और उसी की वजह से इसे तारीफ मिल रही है। भारत में घटी घटनाएँ अगर किसी खुफिया मिशन का टेक-ऑफ प्वाइंट थीं तो उसका रनवे इतना लम्बा न होता तो बेहतर होता। मगर आईसी814 के चाहने वालों का गैंग जिस तरह इस फिल्म पर टूट पड़ा है, वह हैरान करने वाला है।

फिल्म स्कूल के विद्यार्थियों को दोनों फिल्मों की समीक्षा करने वालों के रिव्यू निकालकर उसकी तुलना करनी चाहिए। फिल्म का प्वाइंट ऑफ व्यू बदलते ही नामी समीक्षकों के रिव्यू के पैरामीटर किस तरह बदलते हैं इसे शोधार्थियों को दुनिया के सामने लाना चाहिए।

फिल्म समीक्षकों की दिक्कत ये है कि वो किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप नहीं करा सकते। बडे मीडिया संस्थानों में बैठे समीक्षक एकजुट होकर किसी फिल्म के कारोबार को कुछ प्रतिशत घटा या बढ़ा सकते हैं मगर वे किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने से नहीं रोक सकते।

धुरंधर के आलोचकों में एक और बात साझा दिखती है कि उनमें से ज्यादातर की नजर में पाकिस्तान की आलोचना करने का मतलब है 'मुसलमान' या इस्लाम रिलीजन की आलोचना करना। कुछ समीक्षक चाहते हैं कि आतंकी हमले के बाद 'अल्लाहो अकबर' का नारा लगाया गया तो उसे न दिखाया जाए! उन्हीं समीक्षकों ने 'राम के नाम' डाक्यूमेंट्री की पानी पी-पी कर तारीफ की क्योंकि भगवान राम का नाम लेकर एक ऐसी मस्जिद गिरा दी गयी जो मन्दिर को तोड़कर बनायी गयी थी ताकि हिन्दुओं को अपमानित और दमित किया जा सके मगर वही फिल्ममेकर हजारों बर्बर घटनाओं के बाद भी 'अल्लाह के नाम' बनाने का साहस नहीं कर पाते हैं।

धुरंधर में मुसलमानों के बारे में कोई जेनेरिक स्वीपिंग कमेंट नहीं है, इस्लाम के बारे में भी कोई जेनेरिक स्वीपिंग कमेंट नहीं है। फिल्म पाकिस्तान को भारतीय नजरिये से देखती है और इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। भारतीय होते हुए पाकिस्तान के नजरिये से देखना समस्याप्रद दृष्टिकोण है न कि किसी आतंकवादी वारदात को भारतीय नजरिए से देखना।

धुरंधर के प्रशंसकों ने एक बात रेखांकित की है कि जो लोग कहते थे कि किताब का जवाब किताब से दो, सिनेमा का जवाब सिनेमा से दो, वही अब इस फिल्म को लेकर जनता को गैसलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रोपगैंडा है, मत देखो! मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐस कौन सी फिल्म दुनिया में बनी है जो किसी खास नजरिए का प्रोपगैण्डा नहीं करती है! मेरी राय में तत्वतः 'सत्यमेव जयते' भी एक प्रोपगैण्डा है और 'ईश्वर एक है' भी एक प्रोपगैण्डा ही है।

'कश्मीर फाइल्स' के समय भी मैंने लिखा था कि फिल्म की समस्या ये नहीं है कि वह गलत विषय उठा रही है जिससे ज्यादातर लेफ्टविंग आलोचक बिफरे थे। फिल्म की समस्या थी कि वह बुरी फिल्म थी। धुरंधर फिल्ममेकिंग के हिसाब से अच्छी फिल्म है। मुख्यधारा के समीक्षकों को उसी आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए न कि आइडियोलॉजिकल नरेटिव के चश्मे से। यह काम विद्वानों का है, न कि अखबारी समीक्षा करने वालों का।

ऐसा भी नहीं है कि धुरंधर फ्री-स्पीच की संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण करती है। फिल्म किसी भी जाति, रिलीजन या देश इत्यादि को धरती से मिटा देने की बात नहीं करती है। फिल्म आतंकवाद के मुद्दे को भारतीय नजरिए या फिर अजित डोभाल के नजरिए से पेश करती है और यह किसी तरह का कसूर नहीं है।

दुनिया बदलने से पहले खुद को मजबूत बनाना क्यों जरूरी? संतुलन के साथ जीना और मदद का असली मूल्य समझें

हम सभी को मदद, प्रेम और दया की जरूरत होती है। खुद पर भरोसा होना एक बात है और यह अहम भी है, लेकिन परिवार, समाज, अध्यापक, मित्र आदि की मदद के बगैर हम आमतौर पर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मदद करना और मदद लेना ही मनुष्यता का प्राण तत्त्व है। अगर प्रकृति ने हमें समर्थ, शक्तिवान और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है और ऐसी स्थिति में हमने किसी की थोड़ी-सी भी मदद कर दी, तो संभव है कि यह किसी के जीवन का आधार बन जाए।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, हमारा पद क्या है या हम कितने धनी और समृद्ध हैं। हम चाहे जितने श्रेष्ठ, समृद्ध, ज्ञानी, उद्यमी, जगत विजेता, उच्च पदासीन बन जाएं, लेकिन हमें विभिन्न लोगों की मदद कभी न कभी लेनी पड़ती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आज जो भी हम प्राप्त कर पाए हैं, वह अन्य लोगों की मदद के कारण संभव हुआ है। चाहे वह मदद अत्यंत कम हो, लेकिन मदद तो मदद है।

प्रेम से जताया गया आभार विश्वास भरता है। यह मनोवैज्ञानिक मदद है। किसी की समस्या को सिर्फ सुन लेना भी मानसिक मदद है, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होता है कि कोई उसका मित्र है। अस्पताल में तबियत पूछने जाना, अंक कम आने पर बच्चे को समझाना, अन्य की खुशी के लिए कुछ करना मदद का ही रूप है।

हम जीवन में अक्सर दूसरों की मदद करने, परिवार, समाज और मित्रों की भलाई पर ध्यान देते हुए अपनी लोकप्रिय छवि बनाने के क्रम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत और अपने लिए समय निकालना पीछे छूट जाता है। समाजोपयोगी काम करना आवश्यक है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हमारा अपना स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए। समाज बहुत स्वार्थी है। हो सकता है कि हम दूसरों के लिए या समाज के लिए अपना सर्वोत्तम दे रहे हों, लेकिन जब हमें सर्वाधिक आवश्यकता हो, तो संभव है कि हमारे पास कोई भी न हो। इसलिए मददगार बनने की चाहत रखने वाले को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है।

सतही तौर पर देखें तो ऐसी बातें स्वार्थपरक लग सकती हैं, लेकिन यह सच है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वकेंद्रित होता है। जब तक किसी व्यक्ति को सामने वाले से थोड़ा भी लाभ नहीं होता, तब तक वह उसके लिए त्याग या उसकी मदद नहीं करता। इसे 'परसेप्शन ऑफ रिसोर्सेस' यानी संसाधनों की धारणा सिद्धांत कहा जाता है।

हम किसी की मदद तभी करते हैं, जब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हों, वरना हम अपना स्वार्थ ही सोचेंगे। एक अध्ययन में पाया गया कि लोग मदद या सहायता के लिए

प्रेरित तब होते हैं, जब तक उन्हें लगता है कि इस मदद या दान से उन्हें समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान मिलेगा। इसे 'मॉडल इफेक्ट' या सामाजिक सम्मान की चाह कहा जाता है।

इस सिद्धांत के तहत लोग अक्सर सामने वाले व्यक्ति का पद और स्थिति देखकर मदद करने का निर्णय लेते हैं। वे आकलन करते हैं कि मदद लेने वाले का समाज में क्या दर्जा और स्थिति है। सिर्फ मानवीयता आधारित निर्णय बहुत कम लिए जाते हैं। 'सामाजिक आदान-प्रदान' के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संबंधों में लोग हमेशा 'इनाम-लाभ' का हिसाब रखते हैं। लाभ स्पष्ट होने पर ही व्यक्ति मदद को तैयार होता है। इसलिए मददगार बनते हुए अति भावुकता से बचना उचित है।

आशय यह कि संवेदनशील होना अच्छा है, लेकिन इसे बचाए रखने के लिए विवेक के स्तर पर सजग रहना भी जरूरी है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मदद बिना किसी अपेक्षा के की जाती है, उसी को मदद कहा जा सकता है, क्योंकि यह कोई सौदा नहीं है।

अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का खयाल रखना सिर्फ स्वार्थ नहीं, बल्कि सबसे समझदारी भरा निर्णय है। बीमा, बचत, आपातकालीन निधि का ध्यान रखना उचित है, ताकि किसी संकट में 'सहारे' की कमी हमें अंदर से हिला कर न रख दे। साथ ही अपने लिए जीते हुए शौक जिंदा रखने चाहिए। ध्यान या 'मेडिटेशन', हृदय की बात कहने वाले विश्वसनीय साथी, अपने 'मूड बूस्टर' यानी तनाव दूर करने वाले मित्र, अपनी दिनचर्या, संगीत, लेखन और खेलों पर भी ध्यान देना उचित है।

जब मदद करने वाला खुद स्वस्थ और मजबूत होगा, तभी वह दूसरों के लिए कुछ देने की क्षमता बनाए रख सकेगा। दूसरों की सहायता से पहले सर्वप्रथम खुद को हर दृष्टि से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी की मदद ही न की जाए या स्वार्थी बना जाए। अभिप्राय यह है कि मदद करते हुए अपना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। जहां तक हो सके, हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करते हुए अहंकार, द्वेष या सामने वाले को कमतर दिखाने का भाव भी विकसित नहीं होने देना चाहिए।

इसके अलावा, अगर किसी ने कष्ट काल में हमारी मदद नहीं की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी वही व्यवहार रखें। याद रखना चाहिए कि दुष्टता को दुष्टता से नहीं जीता जा सकता। बुरे के आगे बुरा बनने से बुराई का एक दुर्ग खड़ा हो जाता है और इससे जन्म लेता है युद्ध। बुरों के प्रति भी अच्छाई का भाव रखते हुए मदद करनी चाहिए और यह हमें अंगुलिमाल कथा का गौतम बुद्ध बना देगा।

चलते-फिरते, जाने-अनजाने सभी की मदद करते रहना चाहिए। समाज हमारे रुतबे, पैसे, मकान, अहसान करने की ताकत से नहीं, बल्कि मदद कर सकने के जज़्बे से प्रभावित होता है और उसी को ही हमेशा याद रखता है।

पौष्टिक भोजन अब भी सपना, 42 फीसद लोग खरीद नहीं पाते, आखिर किस दिशा में जा रही है दुनिया?

दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां आर्थिक तरक्की और तकनीक की चमक के बीच भोजन जैसी बुनियादी जरूरत इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रपट बताती है कि दुनिया की बयालीस फीसद आबादी पौष्टिक भोजन पर खर्च नहीं कर पाती। यह केवल गरीबी का आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों, बाजार व्यवस्थाओं और आर्थिक असमानताओं का ऐसा आईना है, जिसमें हमारी सामूहिक विफलता दिखती है। जब भोजन जैसे मानव अधिकार को भी बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो समाज कमजोर होता है, चाहे वह कितना ही विकसित क्यों न दिखे। भारत का विकास ढांचा मजबूत दिख सकता है, पर उसकी बुनियाद में पोषण का अभाव साफ महसूस होता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश पौष्टिक भोजन के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सहारा के दक्षिण वाले अफ्रीकी क्षेत्र में तो हालात इतने खराब हैं कि 60 से 80 फीसद आबादी पौष्टिक भोजन का खर्च ही नहीं उठा सकती। वहीं यूरोप, आस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भोजन की पहुंच बेहतर है, पर वहां असंतुलित आहार, प्रसंस्कृत खाद्य और मोटापे जैसी समस्याएं स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। भारत में भोजन और पोषण का संकट दो ध्रुवों में बंटा दिखता है। ग्रामीण भारत में अब भी कुपोषण, रक्ताल्पता, कम वजन जैसे मामलों का उच्च स्तर पाया जाता है। बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति विशेष चिंता का विषय है।

दूसरी ओर शहरी भारत में खाने की उपलब्धता तो है, पर उसकी गुणवत्ता की समस्या है। समय की कमी, काम का तनाव, और तेज बाजार-चालित संस्कृति ने डिब्बाबंद खाद्य, जंक फूड और मीठे पेयों को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बना दिया है। एक तरफ कुपोषण और दूसरी ओर अतिपोषण, दोनों मिलकर स्वास्थ्य संकट को और जटिल बनाते हैं।

खाद्य महंगाई ने भारतीय रसोई को जिस तरह प्रभावित किया है, वह चिंता का विषय है। दालें, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने संतुलित भोजन की लागत बहुत बढ़ा दी है। एक औसत भारतीय परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा केवल कैलोरी-आधारित भोजन पूरा करने में ही खर्च हो जाता है, जबकि पौष्टिक भोजन की थाली उनकी पहुंच से दूर चली जाती है। यह स्थिति बताती है कि भोजन केवल बाजार व्यवस्था का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत की कृषि अब भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मगर असामान्य बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान में बदलाव ने फसल उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे बाजार में दाम बढ़ते हैं। समस्या नीतिगत प्राथमिकताओं की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अभी भी मुख्य रूप से अनाज-आधारित है, गेहूं और चावल पर केंद्रित है। जबकि शरीर को विविध पोषक तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है।

भारत में फल, सब्जियां, दालें, अंडे और डेयरी जैसे घटक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकारी पोषण कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसी वजह से मध्याह्न भोजन की तरह अन्य योजनाएं भोजन तो देती हैं, पर पूर्ण पोषण सुनिश्चित नहीं कर पातीं। दुनिया के कई देशों ने भोजन को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्राजील का 'शून्य भुखमरी' अभियान इसका उदाहरण है, जिसने स्थानीय कृषि, सबसिडी और पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया।

जापान ने 'शोकू इकु' नीति के तहत बच्चों को भोजन विज्ञान की शिक्षा दी। एक ऐसा ढांचा, जो स्पष्ट करता है कि भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि संस्कृति, समझ और स्वास्थ्य का आधार है। दक्षिण कोरिया ने प्रसंस्कृत खाद्य पर सख्त नियंत्रण लागू किए, जिससे जीवनशैली संबंधी बीमारियों में गिरावट आई। भारत इनसे सीख लेकर अपने कार्यक्रमों को अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बना सकता है।

दरअसल, पोषण की कमी का असर व्यक्तिगत स्तर से कहीं अधिक व्यापक है। यह कार्यक्षमता, शिक्षा और उत्पादकता को प्रभावित करता है। कमजोर और कुपोषित बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुपोषित युवा समाज में सक्रिय योगदान देने में पीछे रह जाते हैं।

यह समझना आवश्यक है कि भोजन कोई साधारण आर्थिक वस्तु नहीं है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार का मूल तत्त्व है। जब एक बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाती, तो समाज के लिए यह अनदेखा करने योग्य आंकड़ा नहीं रह जाता। यह वह बिंदु है, जहां नीतियों, बाजार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य - चारों को मिलकर समाधान तैयार करना होगा।

भारत के पोषण संकट को समझने के लिए एक स्वस्थ थाली में वास्तव में क्या होना चाहिए, यह समझने की जरूरत है। बच्चों की थाली में प्रोटीन (दाल, अंडा, दूध), कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा अनिवार्य हैं। ये तत्त्व न केवल हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि रक्ताल्पता, संक्रमणों की अधिकता, थकान, आंखों की कमजोरी और सीखने की क्षमता में कमी जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं। यह अफसोसनाक है कि भारत के लाखों बच्चों की थाली आज भी इन आवश्यक तत्त्वों से खाली है और इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है।

महिलाओं और वृद्धों के पोषण की जरूरतें इससे भी अधिक विशिष्ट हैं। महिलाओं को विशेष रूप से आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की अधिक मात्रा चाहिए। वहीं वृद्धजन के लिए ओमेगा-3, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक हैं, जो उन्हें हृदय रोग, मधुमेह, हड्डियों के क्षरण और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक संरचना के कारण अक्सर इन्हीं समूहों की थाली सबसे पहले कमजोर होती है, जिससे बीमारी एक स्थायी साथी बन जाती है।

सरकारी नीतियां और जमीनी ढांचा पोषण सुधार का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। देश में आंगनबाड़ी और स्कूल का भोजन कक्ष बच्चों के पोषण का बड़ा आधार माने जाते हैं, पर इनकी स्थिति असमान और अक्सर संसाधन-विहीन नजर आती है। आज भारत के सामने प्रश्न यह नहीं कि भोजन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि यह है कि क्या गुणवत्ता पूरक भोजन सही कीमत और सही समय पर हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है?

भारतीय कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग जिस तेजी से बढ़ा है, वह पोषण संकट का एक और अदृश्य कारण बन रहा है। खेतों में सब्जियां और फलों पर अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव न केवल फसलों की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि लंबे समय में लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इन रसायनों का अंश खाद्य पदार्थों में बचा रह जाता है, जिससे बच्चों में तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, महिलाओं में हार्मोन असंतुलन और वयस्कों में कैंसर और गुर्दा रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस क्षेत्र में न तो निगरानी सख्त है, न ही किसानों को सुरक्षित विकल्पों की पर्याप्त जानकारी मिल पाती है। जैविक खेती और कम-रसायन जैसे विकल्पों की चर्चा तो होती है, पर जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच नगण्य है। अगर राष्ट्र एक मजबूत, सक्षम और स्वस्थ भविष्य चाहता है, तो भोजन को बाजार का उत्पाद नहीं, बल्कि सार्वभौमिक अधिकार घोषित करना होगा। तभी वास्तविक विकास की नींव मजबूत होगी।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत थाने पर आई महिलाओं को किया जागरूक

प्रयागराज। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज की मिशन शक्ति टीम द्वारा थाने पर अपनी समस्या को लेकर आई महिलाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर 101 आदि के बारे में जानकारी दी गई, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया गया।

दशाश्वमेध घाट पर दीपोत्सव की भव्य चमक दीपावली को यूनेस्को मान्यता मिलने का हुआ उत्सव

प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुरुवार की शाम दशाश्वमेध घाट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में संगम तट दीपों की रौशनी से दैदीप्यमान हो उठा।

घाट पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए, जिनसे स्वास्तिक और यूनेस्को के प्रतीक चिह्न की आकर्षक आकृतियाँ निर्मित की गईं। दीपों से सजा घाट बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रहा था।

इस अवसर पर महापौर गणेश केसरवानी ने दीप प्रज्ज्वलित करते हुए कहा, 'दीपावली के विश्व स्तर पर मान्यता मिलने से भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा है। दीपावली पर्व भगवान श्री राम जी द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। लगभग 550 वर्ष बाद अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्माण मंदिर की स्थापना हुई और धर्मध्वजा फहराई गई। यही कारण है कि दीपावली हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। प्रयागराज में आयोजित यह दीपोत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं का जीवंत प्रतीक है।'

केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने कहा, 'एक ओर काशी-तमिल संगमम 4.0 का आयोजन चल रहा है और दूसरी ओर दीपावली का यूनेस्को की विश्व अमूर्त धरोहर सूची में शामिल होना यह एक सुखद संयोग है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।' अयोध्या और वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत वहाँ भी दीपोत्सव मनाया गया।

जोन यमुनानगर कमिश्नरेट की मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक

प्रयागराज। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत जोन यमुनानगर कमिश्नरेट प्रयागराज की मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को थाना क्षेत्र के स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर 101 आदि के बारे में जानकारी दी गई, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया गया ।

सांसद ने सिने स्टार धर्मेंद्र के प्रार्थना सभा में हुई शामिल, दी श्रद्धांजलि

एक युग का अंत, एक विरासत अमर : सांसद सीमा द्विवेदी

सांसद ने सांसद और सिने स्टार हेमामालिनी, बेटियों को दी सात्वना

प्रयागराज / नई दिल्ली। सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने आज नई दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में हिंदी सिनेमा के महानतम कलाकार, सबके चहेते सिने स्टार धर्मेंद्र की स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुई। उन्होंने सांसद और सिने स्टार हेमामालिनी, उनकी बेटियों और परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया।

सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने कहा कि यह पल अत्यंत भावुक और गरिमामय था। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता लेकिन इस सभा में उपस्थित होकर, उनके परिवार, सहकर्मियों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देना, उनके अद्भुत जीवन और बेमिसाल करियर को याद करना एक सच्चा सम्मान था। सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने कहा कि सिने स्टार धर्मेंद्र जी सिर्फ़ एक अभिनेता नहीं थे; वह करोड़ों दिलों की धड़कन थे, जिन्होंने अपनी सादगी, दमदार अभिनय और मानवीय गर्मजोशी से पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके 'ही-मैन' वाले अंदाज़ से लेकर उनकी रूमानी अदाओं तक, उनकी हर छवि आज भी सिनेमा प्रेमियों के ज़हन में ताज़ा है।

पीएम पोषण योजना के अन्तर्गत बच्चों को वितरित की गई मूंगफली की चिक्की

प्रयागराज । पीएम पोषण योजनान्तर्गत शुक्रवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजौना जसरा प्रयागराज में उपस्थित सभी बच्चों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री के रूप मूंगफली की चिक्की का वितरण किया गया। ध्यातव्य है कि सरकार ने ठंड में माह दिसम्बर से लेकर मार्च माह तक सप्ताह में एक दिन गुरुवार को मूंगफली के चिक्की वितरण का आदेश दिया है।अतिरिक्त पोषण खाद्य सामग्री मिलने से बच्चे बहुत खुश थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी ने बताया कि सरकार ने फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत वृहस्पतिवार को अतिरिक्त खाद्य सामग्री के रूप में गत वर्ष से चिक्की वितरण की योजना शुरू किया गया है।इस अवसर पर विद्यालय के भारतेन्द्र त्रिपाठी, सुनील कुमार शुक्ल, इरफ़ान अहमद, नाज़िया सुल्ताना, जितेन्द्र कुमार शर्मा, आशीष कुमार गुप्ता, शरद कुमार, शिशिर जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

समाजसेवी मनप्रीत कौर माघ मेला में शुरू करेगी विशाल भण्डारा

कई सेक्टरों में चल रही है विशाल भण्डारे की तैयारियां

प्रयागराज। मां सीता रसोई की डायरेक्टव श्रीमती मनप्रीत कौर की ओर से माघ मेला क्षेत्र में पहली बार कई सेक्टरों में विशाल भण्डारा इस बार से चलाया जाएगा, जहां हजारों श्रद्धालुओं को दिन - रात चाय, नाश्ता, खाना और गर्म कपडे मिलेगे। मां सीता रसोई की डायरेक्ट, युवा उधमी श्रीमती मनप्रीत कौर की ओर से माघ मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पहली बार नाश्ता और खाने की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने जा रही है।

वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती मनप्रीत कौर इसके पूर्व कई वर्षो से अयोध्या में सीता मां की रसोई, वृन्दावन में कई स्थानों पर विशाल भण्डारा चला रही है।

उन्होंने बताया कि इसके पूर्व तीर्थराज प्रयागराज के महाकुम्भ -2025 में कई स्थानों पर विशाल भण्डारा दिन, रात चलाकर लाखों श्रद्धालुओं को चाय, नाश्ता, खाना और गर्म कपडे दिए थे। श्रीमती मनप्रीत कौर ने बताया कि त्रैम्बकेश्वर (नाशिक) कुंभ, हरिद्वार कुंभ और सिंहस्थ महाकुम्भ उज्जैन में भी विशाल भण्डारा चलाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गयी है जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को चाय, नाश्ता, खाना और गर्म कपडे मिल सके। उन्होंने बताया कि समाज सेवा अब जिन्दगी का लक्ष्य बन गया है इससे सुकून और शांति मिलती है।

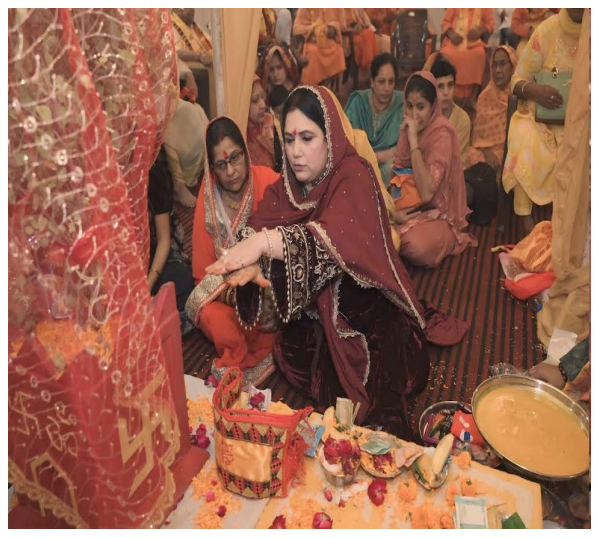

पीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर, बाउंड्री वाल ध्वस्त

थरवई (प्रयागराज)। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को थरवई क्षेत्र के जगदीशपुर पूरे चंदा मजरा चक ठाकुर राम में अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की। करीब डेढ़ बीघे भूमि पर चारों ओर बनाई गई बाउंड्री वाल को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया।कार्रवाई के दौरान पीडीए के जेई महेश कुमार शुक्ला, नीतू मिश्रा, सुभाष मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने बुलडोजर लगाकर पूरी बाउंड्री को गिरायापीडीए अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृति किए जा रहे ऐसे निर्माणों पर आगे भी अभियान चलता रहेगा।

जमीनी विवाद में दंपति से मारपीट, दोनों घायल

थरवई (प्रयागराज)। थरवई थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर गुरुवार सुबह दंपति से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी राजकुमार और उनकी पत्नी संगीता देवी पर विपक्षी राजित राम सहित अन्य लोगों ने जमीनी विवाद में गुरुवार सुबह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हैघटना के बाद पीड़ित दंपति किसी तरह थरवई थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है थरवई पुलिस मामले की जांच कर रही है।

माघ मेला प्रयागराज का लोगो जारी, लोगो में सूर्य, चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है जो प्रयागराज में माघ मेले का बनता है कारक सनातन धर्म के लिए है सुखद : स्वामी ब्रह्मश्रम महराज

प्रयागराज। माघ मेले के इतिहास में पहली बार मेले के दर्शन तत्त्व को परिलक्षित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से माघ मेले का लोगो आज जारी किया गया है। इस लोगो के अन्तर्गत तीर्थराज प्रयाग, संगम की तपोभूमि तथा ज्योतिषीय गणना के अनुसार माघ मास में संगम की रेती पर अनुष्ठान करने की महत्वता को समग्र रूप से दर्शाया गया है।

सर्वप्रथम लोगो में सूर्य एवं चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है जो प्रयागराज में माघ मेले का कारक बनता। भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा 27 नक्षत्रों की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूर्ण करता है। माघ मेला इन्हीं नक्षत्रीय गतियों के अत्यंत सूक्ष्म गणित पर आधारित है। जब सूर्य मकर राशि में होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माघी या अश्लेषा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रों के समीप होता है, तब माघ मास बनता है और उसी काल में माघ मेला आयोजित होता है।

चंद्रमा की 14 कलाओं का संबंध मानव जीवन, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा और आध्यात्मिक साधना से माना गया है। माघ मेला चंद्र-ऊर्जा की इन कलाओं के सक्रिय होने का विशेष काल भी है। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा की वृद्धि (शुक्ल पक्ष) साधना की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माघ स्नान की तिथियाँ चंद्र कलाओं के अत्यंत सूक्ष्म संतुलन पर चुनी जाती हैं।

माघ महीने की ऊर्जा (शक्ति) अनुशासन, भक्ति और गहन आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ी होती है क्योंकि यह महीना पवित्र नदियों में स्नान, दान, तपस्या और कल्पवास जैसे कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति को निरोगी बनाते हैं और उसे दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं।

प्रयागराज का अविनाशी अक्षयवट, जिसकी जड़ों में भगवन ब्रह्मा जी का, तने में भगवन विष्णु जी का एवं शाखाओं और जटाओं में भगवन शिव जी का वास है, उसके दर्शन मात्र से मोक्ष मार्ग सरल हो जाता हैं। इसी कारण कल्पवासियों में उसका स्थान अद्वितीय है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हैं अतः महात्मा का चित्र इस देव भूमि में सनातनी परम्परा को दर्शाता है जहां चिर काल से ऋषि-मुनि आध्यात्मिक ऊर्जा हेतु आते रहे हैं।

माघ मास में किए गए पूजन एवं कल्पवास का पूर्ण फल संगम स्नान के उपरांत श्री लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन से प्राप्त होता हैः अतः लोगों पर उनके मंदिर एवं पताका की उपस्थिति माघ मेले में किए गए तप की पूर्णताः की व्याख्या करता है। संगम पर साइबेरियन पक्षियों की उपस्थिति यहाँ के पर्यावरण की विशेषता को दर्शाता है। लोगो पर श्लोक 'माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् ततः' का अर्थ है माघ के महीने में स्नान करने से सभी पाप मुक्ति हो जाती है। यह लोगो मेला प्राधिकरण द्वारा आबद्ध किए गए डिजाइन कंसल्टेंट अजय सक्सेना एवं प्रागल्भ अजय ने डिजाइन किया ।

अखिल भारतीय दण्डी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मश्रम महराज ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के लिए शुभ और सुखद संदेश है।

मंगल लक्ष्मी में फराह खान और दिलीप ने बढ़ाया पहले स्वाद चैलेंज का तड़का

प्रयागराज। अपनी चुटकियों और ट्रेडमार्क तड़के के साथ फिल्ममेकर फराह खान इंटरनेट फेवरेट दिलीप के साथ कलर्स के मंगल लक्ष्मी में एक स्पेशल एपिसोड के लिए पहुंचीं, जहाँ किचन डांस और अनोखे कुकिंग टास्क से जीवंत हो गया। चल रहे ट्रैक में 'पहला स्वाद' प्रतियोगिता अपने सबसे निर्णायक चरण में है टिकट-टू-फिनाले चैलेंज जहाँ नई हेड शेफ भाभीजी (नीलू वागेला) मंगल और सौम्या को अप्रत्याशित कुकिंग टेस्ट में लगा देती हैं। जैसे ही फराह और दिलीप एक रोमांचक 'जोड़ी चैलेंज' पेश करते हैं, सौम्या आदित के साथ टीम बनाती है और मंगल को अकेले ही मुकाबला करना पड़ता है। अब, फिनाले साफ नजर आने के साथ सवाल यह है क्या मंगल ऐसा डिश दे पाएगी जो न सिर्फ जजों के दिल जीत ले बल्कि प्रतियोगिता में उसकी जगह पक्की कर दे?

कलर्स के मंगल लक्ष्मी के एक खास एपिसोड की शूटिंग के दौरान फराह खान ने कहा, 'अरे भाई, जब किचन का महायुद्ध हो रहा हो मंगल लक्ष्मी में, मुझे तो आना ही था! मैं सुपर एक्साइटेड हूँ 'पहला स्वाद' टिकट-टू-फिनाले चैलेंज जज करने के लिए यहाँ खाने का टेस्ट भी होगा और कंटेस्टेंट्स का पेशन्स भी। अपने फुल-ऑन फराह-तड़का के साथ, थोड़ी मस्ती, थोड़ा मसाला, और हमारे कुक दिलीप का जुड़ना किचन गारंटीड गरम होने वाला है। मंगल और सौम्या दोनों को मिलेंगे सरप्राइज और शॉक, लेकिन असली विनर का स्वाद कौन परोसेगा, वो तो आपको देखना होगा। बस इतना कहूँगी यह एपिसोड फ्लेवर, फन और फुल-ऑन फायरवर्क्स सर्व करता है।'

जॉनसन्स बेबी के निर्माता ने 2 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी के प्रशिक्षण का समर्थन किया

प्रयागराज। हर मां अपने बच्चे के जन्म के पहले क्षणों की मीठी यादें हमेशा संजोकर रखती है, जैसे, बच्चे का पहली बार रोना, पहला स्पर्श, पहली बार बच्चे को देख पाना। दुर्भाग्य से, कुछ माताएं इस अनुभव से वंचित रह जाती हैं, खास तौर पर जन्म के समय सांस अटक जाने जैसी स्थितियों में, जो समय से पहले मौत का कारण बनती हैं। पीढ़ियों से माता-पिता के साथ साझेदारी निभाते रहे ब्रांड, जॉनसन्स बेबी ने पिछले 16 साल से एक प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ संघ द्वारा संचालित नवजात पुनर्जीवन (नियोनेटल रिससिएशन प्रोग्राम-एनआरपी) प्रशिक्षण का समर्थन कर रहा है। यह पहल जॉनसन्स बेबी की जीवन के पहले क्षण से शिशुओं की सुरक्षा में प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। एसेन्शियल हेल्थ एंड स्किन हेल्थ और मार्केटिंग उपाध्यक्ष, केनव्यू, भारत, मनोज गाडगिल, बिज़नेस यूनिट हेड ने कहा, 'नवजात शिशु की सुरक्षा उस पहले मिनट के उचित हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। दुर्भाग्य से पर्याप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी के कारण यह अक्सर प्रभावित होती है।

15 से 20 दिसम्बर के बीच शिविर लगाने को आवंटित होगी जमीन

मेलाधिकारी ऋषिराज ने कहा कि जमीन आवंटन के बाद बची जमीन नयी संस्थाओं को होगी आवंटित

प्रयागराज। माघ मेला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों और अन्य संस्थाओं को जमीन आवंटन का शेड्यूल आज जारी कर दिया है। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि 15 दिसंबर से 20 दिसम्बर के बीच विभिन्न सेक्टरों में मेला प्रशासन जमीन का आवंटन करेगा। उन्होंने बताया कि

15 दिसंबर को अरैल, नागवासुकी मार्ग, हरिश्चंद्र मार्ग पर बसने वाली संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि 16 दिसंबर को प्रयागवाल यानि तीर्थ पुरोहितों को जमीन का आवंटन किया जाएगा, 16 दिसंबर को गंगोली शिवाला मार्ग, ओल्ड जीटी मार्ग, अलोप संकरी मार्ग और तुलसी मार्ग पर बसने वाली संस्थाओं को जमीन का आवंटन होगा। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को सामियामाई मार्ग, सूरदास मार्ग, गणपति मार्ग और कबीर नगर में जमीन का आवंटन होगा। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि 18 दिसंबर को अक्षय वट मार्ग, संगम वापसी मार्ग, लाल सड़क, परेड, हर्षवर्धन मार्ग, अन्नपूर्णा और रामानुज मार्ग में बसने वाली संस्थाओं को जमीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग, संगम अपर मार्ग, सरस्वती मार्ग, महावीर मार्ग, मोरी मार्ग, गाटा मार्ग और अन्य संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। 20 दिसंबर को समुद्रकूप मार्ग और इंटरलॉकिंग मार्ग, सेक्टर 4 भारद्वाज मार्ग, संगम लोअर मार्ग और शास्त्री गाटा में बसने वाली संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि अब तक सिर्फ दंडी बाडा, आचार्य बाड़ा और खाक चौक को जमीन आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जमीन बचने के बाद नयी संस्थाओं को जमीन आवंटित होगी।

भिवंडी के पड़घा में डॉग बाइट से 5 वर्षीय मासूम की मौत

सरकारी अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप; ग्रामीणों में आक्रोश

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

तालुका के पड़घा, बोरीवली गांव में आवारा कुत्ते के काटने के बाद 5 वर्षीय राहिल रियाज़ शेख की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर लापरवाही, वैक्सीन की कमी और इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। शनिवार को बच्चे को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक करने के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पड़घा सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा किया।

घटना 20 नवंबर की शाम की है। आवारा कुत्ते ने राहिल को काट लिया, जिसके बाद उसे पड़घा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि यहां एंटी-रेबीज़ वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल ने दो इंजेक्शन देकर बच्चे को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दो और इंजेक्शन दिए गए। पांचवें इंजेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण परिवार उसे अलग-अलग अस्पतालों में लेकर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी वैक्सीन नहीं मिली। इसी बीच बच्चे की हालत बिगड़ती गई और हालत गंभीर होने पर उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल फिर कस्तूरबा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई।परिजन रियाज़ शेख ने कहा कि अगर समय पर इंजेक्शन और उचित इलाज उपलब्ध होता, तो उनका बच्चा बच सकता था। गांववालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में 20 से 30 बच्चे कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। आरोप है कि बाहरी क्षेत्रों से कुत्तों को पकड़कर पड़घा में छोड़ दिया जाता है, जिससे यहां हमले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि सरकारी अस्पताल में न तो वैक्सीन मिलती है, न डॉक्टर समय पर उपलब्ध होते हैं और कई बार एम्बुलेंस भी नहीं मिलती।पड़घा सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रदीप अशोक पाटिल ने बताया कि राहिल को 20 नवंबर को ग्रेड-3 डॉग बाइट के साथ लाया गया था और ऐसे मामलों में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देना जरूरी होता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए बच्चे को भिवंडी रेफर किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार बाद के इंजेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन 9 दिसंबर को जब वह फिर अस्पताल लाया गया, तब रेबीज़ के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे थे। ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच नासिर रफीक शेख, बच्चे के चाचा अरबाज़ शेख और स्थानीय युवक वक़ास नाचन ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में वैक्सीन नहीं होने से परिजन लगातार भटकते रहे, और इसी लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती और वैक्सीन समय पर उपलब्ध होती, तो राहिल की जान बचाई जा सकती थी।घटना के बाद गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर रोक लगाने, रेबीज़ वैक्सीन की निश्चित उपलब्धता, डॉक्टरों की नियमित तैनाती और एम्बुलेंस सुविधा सुचारू करने की मांग की है।

नागाव से 13 वर्षीय लड़की लापता

सुबह घर से निकली और वापस नहीं लौटी।अज्ञात व्यक्ति पर बहलाकर ले जाने का शक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर के नागाव क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, बच्ची 9 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हो सकता है।लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर से बाहर जाने के बाद अचानक गायब हो गई। परिवार ने आसपास के इलाकों में उसकी काफी तलाश की,लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। चूंकि वह नाबालिग है और कई घंटों बाद भी वापस नहीं लौटी, इससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। इसी आधार पर पुलिस ने

भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शांतिनगर पुलिस ने बच्ची की खोज शुरू कर दी है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक एस. बी. कुचेकर कर रहे हैं।

मटका जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई में नकदी और जुए का सामान बरामद

भिवंडी। शहर के खाड़ीपार पुल के पास मटका जुआ खेल रहे दस लोगों को निजामपुर पुलिस ने रंगेहाथों पकड़ा है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुगार

प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान जुआ अड्डे से 4,200 रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाला साहित्य बरामद किया गया।निजामपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस नाईक दत्तात्रय कांबले द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, खाड़ीपार पुल से पहले समीर सर्विस सेंटर के नजदीक कुछ लोग लंबे समय से मटका जुआ गतिविधियों में शामिल थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया।गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रज्जब अली लाल मोहम्मद अंसारी, जोगेंद्र रामसुख चव्हाण, मुस्तकीम अब्दुल मजीद अंसारी, गणेश गोडाबू देवनार, लाला राजेंद्र प्रसाद पासवान, राजू शिवनाथ मिश्रा, परवेज मुस्तफा अंसारी, महेन्द्र सरजू प्रसाद यादव, मुर्तज़ा जमाल शेख और सुभाष काशीराम यादव शामिल हैं।पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी अवैध रूप से मटका जुआ खेलते पाए गए, जिसके बाद महाराष्ट्र जुगार कानून की धारा 12(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को नोटिस देकर रिहा कर दिया है।निजामपुर पुलिस आगे की जांच जारी रखे हुए हैं।

पडघा-बोरिवली में एटीएस व ईडी की छापेमारी...

दहशतवादी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेनदेन के सुराग मिलने के बाद कई घरों पर कार्रवाई

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। दहशतवादी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेनदेन के एक मामले में सुरक्षा एजेंसियों को मिले महत्वपूर्ण इनपुट के बाद गुरुवार तड़के एटीएस और ईडी की संयुक्त टीम ने भिवंडी तालुका के पड़घा-बोरिवली गांव में छापेमारी की। जांच के दौरान सामने आया कि यह गांव करीब 25 वर्षों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के रडार पर है। वर्ष 2002 और 2003 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इसी गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसी आरोपी का पुत्र भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था, जिसे 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया,एजेंसियों ने बताया कि पड़घा-बोरिवली गांव पर कार्रवाई इसलिए भी तेज की गई है क्योंकि यहां एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े संदिग्ध ने स्वतंत्र कैबिनेट, स्वतंत्र राष्ट्र और अलग संविधान का मसौदा तक तैयार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि इस दौरान कई युवाओं को कट्टर गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। करीब तीन महीने पहले इसी इलाके से दो अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं के बाद यह गांव खुफिया एजेंसियों की नजर में अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाने लगा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गांव के कुछ युवाओं को प्रतिबंधित संगठन में शामिल किया गया था और उन्हें हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने की भी आशंका है। विदेश में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर आरोपी प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक मासिक पत्रिका में भड़काऊ सामग्री तैयार कर रहे थे। यह जानकारी एनआईए की जांच में सामने आई है।इस वर्ष जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकीब नाचन सहित 22 लोगों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 19 मोबाइल फोन, कट्टरपंथ से जुड़ा साहित्य और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे। लगभग दो वर्ष पहले भी एनआईए ने इसी गांव में कई संदिग्धों के घरों पर छापे मारे थे। एनआईए द्वारा गिरफ्तार साकीब नाचन का इसी वर्ष जून में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। एजेंसियों की इस ताज़ा कार्रवाई के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है तथा कई लोगों से पूछताछ जारी है।

भिवंडी तेलुगु मंच की ओर से गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार...

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी के बालाजी नगर में स्थित प्रसिद्ध समाजसेवक कोडम लक्ष्मीनारायण की सुपुत्री कुमारी विजया कोडम ने दिल्ली के एमिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स डिफेन्स एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज किया है। उनका दिनांक 7 दिसंबर को दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुमारी विजया लक्ष्मीनारायण कोडम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और डीएम प्रोफेसर श्रीमती डॉ. बलविंदर शुक्ला और अन्य कई मान्यवरों के शुभ हाथों से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में विजया के पूरे परिवार भी उपस्थित थे। इसी प्रकार उनकी दूसरी लड़की संध्या कोडम ने असिस्टंट प्रोफेसर की स्टडी करके अपने माता-पिता और समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे माहौल में भिवंडी शहर के तेलुगु और पद्मशाली समाज बांधव के साथ अन्य लोगों से शुभेच्छाओं का वर्षाव हो रहा है।

इसी के उपलक्ष्य में भिवंडी तेलुगु मंच के अध्यक्ष श्रीनिवास सिरीमल्ले जी ने संध्या और विजया को शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गड्डम स्वामी, कोडम लक्ष्मीनारायण और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा, अवैध गतिविधियों में 23 गिरफ्तार

महिलाओं से जबरन अश्लील नृत्य कराने और ग्राहकों से वसूली का आरोप

भिवंडी। भिवंडी तालुका के काल्हेर गांव स्थित सुकून ऑर्केस्ट्रा बार एंड रेस्टोरेंट में चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ नारपोली पुलिस ने मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में बार मालिक, मैनेजर, कैशियर, वेटर, आठ महिला सिंगर तथा दस ग्राहकों सहित कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, 2 फरवरी 2024 की रात करीब 12:30 बजे पुलिस टीम ने बार में दबिश दी। छापे के दौरान यह पाया गया कि बार मालिक हरीश सीना पुजारी, मैनेजर दुरई गणपति पांडियान, कैशियर पुष्पेन्द्र कुमार तिवारी, वेटर प्रफुल माजी, कैलास सेनापति तथा महिला बार बालाओ ने मिलकर ग्राहकों के साथ अश्लील नृत्य

और अनुचित गतिविधियों को बढ़ावा दिया था।शिकायतकर्ता के बयान में बताया गया कि बार में महिलाओं से अवैध रूप से डांस करवाया जा रहा था और इसके बदले ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बार संचालक महिलाओं पर दबाव बनाकर उन्हें ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। महिलाओं के आर्थिक शोषण के भी प्रमाण मिले हैं। छापे के दौरान पुलिस ने 20 हजार रुपये की नकदी सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। सभी 23 आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे की जांच नारपोली पुलिस द्वारा जारी है।

भिवंडी - कल्याण नाका सड़क चौड़ीकरण के चिन्हांकन के खिलाफ नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन

भिवंडी। भिवंडी शहर में कई सड़कों पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। पहले चरण में 17 नवंबर से अंजुर फाटा और कल्याण नाका के बीच दोनों लेन पर 36 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद, अब दूसरे चरण में कल्याण नाका और टेमघर के बीच सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। स्थानीय लोग शुरू से ही इस सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं, वहीं मनपा प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए इस सड़क पर स्थित संपत्तियों की गिनती और निशानदेही का काम शुरू कर दिया है।गुरुवार को जब मनपा के कर्मचारी पुलिस सुरक्षा में राजनोली बाईपास से सड़कों की माप और चिन्हित का काम कर रहे थे, तभी कल्याण रोड के स्थानीय संपत्ति मालिक, व्यापारी और

निवासी टेमघर में जमा हो गए और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए काम रोक दिया। इससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इसके बाद और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को शांत किया। इस बीच, मनपा के सहायक आयुक्त माणिक जाधव ने बताया कि यहां सड़कों की माप और निशानदेही का काम सोमवार से पुलिस सुरक्षा में फिर से शुरू किया जाएगा।

फ्लैट दिलाने के नाम पर 32 लाख की ठगी, बिल्डर पर केस दर्ज

कशेली क्षेत्र में ब्रोकर से लाखों रुपये वसूलने के बाद न फ्लैट दिया, न रकम लौटाई

भिवंडी।भिवंडी तालुका के कशेली गांव क्षेत्र में एक बिल्डर द्वारा ब्रोकर से की गई ठगी का मामला प्रकाश में आया है। नारपोली पुलिस ने इस संबंध में बिल्डर सुशील मनोहर गायकर (36) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 318(2) के तहत मामला दर्ज किया है। काल्हेर गांव निवासी दीपक बडू पाटिल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी बिल्डर ने रिद्धि-सिद्धि फेज-1 स्थित बिल्डिंग नंबर 11 के चैत्राली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 407 और 408 दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे में शिकायतकर्ता ने 22 फरवरी 2023 से 11 अप्रैल 2025 के बीच गूगल पे के माध्यम से कुल 32,06,631 रुपये आरोपी को सौंप दिए। पीड़ित का कहना है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद बिल्डर ने न तो कोई फ्लैट उपलब्ध कराया और न ही रकम वापस की। जब शिकायतकर्ता ने पैसे लौटाने की मांग की, तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित ने नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक राहुल पाटिल द्वारा की जा रही है।

जमीन विवाद को लेकर दो गुट आमने-सामने, लाठी-डंडों से हमला; चार घायल, दो मामले दर्ज

भिवंडी। तालुका के पिंपलास क्षेत्र में बुधवार सुबह जमीन के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच हुई तीखी झड़प में लाठी-डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद कोनगांव पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली शिकायत पिंपलास निवासी मंगेश सुदाम घरत ने दर्ज कराई। उनके अनुसार, सुबह करीब 9:30 बजे वह अपनी पैतृक जमीन पर मौजूद थे, तभी पंकज विट्ठल घरत, बालू घरत, कालीराम घरत, सोग्या घरत और अन्य लोग वहां पहुंचे। कहासुनी बढ़ने पर आरोपियों ने लकड़ी के डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में मंगेश घरत, भाऊ नागरे और प्रतीक मे चापर सहित तीन लोग घायल हुए।दूसरी शिकायत बालू विट्ठल घरत ने दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगेश घरत, सुदाम घरत, नागेश घरत और हरीश घरत सहित कई लोग जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे और मौके पर मौजूद महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की की। आरोपियों ने लकड़ी के डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।कोनगांव पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। झड़प में घायल हुए चार लोगों का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। दोनों प्रकरणों की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अनिल धुमसे कर रहे हैं।

रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भारतीय क्रिकेटरों पर लगाए गंभीर आरोप, विदेश जाकर करते हैं गलत काम!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए कुख्यात रिवाबा ने इस बार टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि कई भारतीय क्रिकेटर विदेश दौरों पर गलत आदतों में लिप्त होते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पति रविंद्र जडेजा की ईमानदारी, अनुशासन और चरित्र की जमकर तारीफ की।

गुजरात विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखने वाली रिवाबा जडेजा को पहले भी उनके बयानबाजी के कारण मीडिया का ध्यान मिला है। मंत्री बनने के बाद उनका यह नया बयान खेल जगत और राजनीतिक दुनिया, दोनों में हलचल पैदा कर रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जब विदेशी दौरों पर जाती है, तो कई खिलाड़ी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों से साफ था कि वह टीम इंडिया के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगा रही थीं।

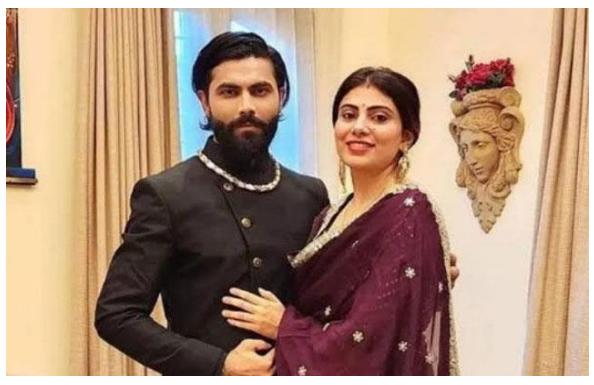

रिवाबा ने अपने पति की अनुशासनप्रियता की तुलना बाकी खिलाड़ियों से करते हुए कहा कि जडेजा दुनिया भर के देशों–लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में लगातार टीम के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी तरह के व्यसन या अनुचित गतिविधि में खुद को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जडेजा का जीवन पूरी तरह संयमित है और वे अपने करियर, परिवार और जिम्मेदारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

अपने बयान को स्पष्ट करते हुए रिवाबा ने कहा कि यह नहीं है कि जडेजा को किसी तरह की रोक-टोक है। चाहे तो वे भी बाकी खिलाड़ियों की तरह मनमानी कर सकते हैं, लेकिन उनका चरित्र और जिम्मेदारी उन्हें गलत चीजों से दूर रखते हैं। रिवाबा के मुताबिक, जडेजा अपने प्रोफेशन को गंभीरता से लेते हैं और इसलिए खुद को अनुशासित रखना पसंद करते हैं।

रिवाबा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। कई लोग उनके दावे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि बिना नाम लिए पूरी टीम को कटघरे में खड़ा करना निश्चित रूप से विवाद को जन्म देगा।

डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम! 90.37 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गुरुवार को तेज गिरावट का शिकार हुआ और 43 पैसे लुढ़ककर 90.37 के अबतक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के मार्च 2026 तक टलने की खबरों के बाद कारोबार के दौरान रुपए पर दबाव और बढ़ा, जिसके चलते यह इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में एक समय 54 पैसे टूटकर 90.48 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंचा।

करेंसी ट्रेडर्स के अनुसार, व्यापार समझौता आगे खिसकने की संभावना ने निवेशकों के बीच रिस्क-ऑफ सेंटीमेंट बढ़ाया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के बयान के बाद बाजार में यह धारणा मजबूत हुई कि सौदा अब मार्च 2026 तक ही पूरा हो पाएगा।

इसके साथ ही आयातकों की ओर से डॉलर की बढ़ी मांग, मैक्सिको द्वारा भारत और एशियाई देशों पर 50इ तक आयात शुल्क लगाने की घोषणा, तथा ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव ने भी रुपये पर दबाव डाला।

रुपये ने आज 89.95 पर शुरुआत की थी लेकिन जल्दी ही कमजोर होकर 90.48 के स्तर तक फिसल गया। पिछला बंद भाव 89.87 प्रति डॉलर था।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी हेड और ईडी अनिल कुमार भंसाली के मुताबिक, 'सीईए की टिप्पणी के बाद रुपये में तेज गिरावट आई। मैक्सिको के नए आयात शुल्क और ऊंचे बॉन्ड यील्ड के चलते इइ द्वारा ऋण बाजार में बिकवाली ने भी रुपया कमजोर किया।' वैश्विक मोर्चे पर, फेडरल रिज़र्व की दर कटौती और नरम संकेतों के बाद डॉलर इंडेक्स 0.17इ टूटकर 98.61 पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 1.17इ गिरकर 61.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे आयात बिल पर आंशिक राहत मिल सकती है।

घरेलू शेयर बाजारों में आज तेजी रही–सेंसेक्स 443.66 अंक चढ़कर 84, 834.93 पर और निफ्टी 141.05 अंक मजबूत होकर 25, 899.05 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, बुधवार को एफपीआई ने 1, 651.06 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी, जिसका दबाव रुपये पर बना हुआ है।

भारत में असमानता का नया रिकॉर्ड!
10 फीसदी लोगों के पास देश की 65 फीसदी दौलत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ताज़ा वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में अमीरी और गरीबी का फासला बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। देश की 65इ संपत्ति शीर्ष 10इ लोगों के पास केंद्रित है, जबकि नीचे के 50इ लोगों के पास केवल 6.4इ संपत्ति है। रिपोर्ट को अर्थशास्त्री लुकास चैंसेल, रिकार्डो गोमेज़-कारेरा, रोवाइदा मोश्रिफ और थॉमस पिकेट्टी ने तैयार किया है। सबसे अमीर 1इ भारतीयों के पास देश की लगभग 40इ संपत्ति है, जो आर्थिक असमानता की गहराई को उजागर करता है।

रिपोर्ट बताती है कि देश की 58इ आय टॉप 10इ लोग कमाते हैं, जबकि नीचे के 50इ लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 15इ आय है। 2014 से 2024 के बीच आय असमानता में मामूली वृद्धि हुई है–यह अंतर 38इ से बढ़कर 38.2इ पर पहुंचा है।

भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सिर्फ 15.7इ है और पिछले एक दशक में इसमें खास सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बड़ी आबादी, जो 1980 में मध्य वर्ग में थी, अब आर्थिक रूप से नीचे के 50इ हिस्से में खिसक गई है।

वैश्विक स्तर पर असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया की कुल संपत्ति रिकॉर्ड स्तर पर है लेकिन इसका फायदा बहुत कम लोगों को मिला है। दुनिया के सिर्फ 60, 000 लोगों (0.001इ) के पास उतनी संपत्ति है, जितनी वैश्विक आबादी के निचले 50इ के पास मिलकर भी नहीं है।

1995 में दुनिया की कुल संपत्ति में अल्ट्रा-रिच 0.001इ की हिस्सेदारी 3.8इ थी, जो 2025 तक बढ़कर 6.1इ होने का अनुमान है। वहीं, गरीब आधी आबादी की संपत्ति 20 वर्षों से लगभग 2इ पर स्थिर है।

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर 10इ लोग 77इ कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि सबसे गरीब 50इ आबादी का योगदान सर्फि 3इ है। अमीर लोग अपनी जीवनशैली और निवेश दोनों के जरिए जलवायु संकट को बढ़ावा देते हैं।

हार के बाद रियल मैड्रिड के खिलाड़ी हुए बेकाबू, कई प्लेयर्स पर लगे प्रतिबंध

मैड्रिड **(एजेंसी)**। सेल्टा विगो से हार के बाद रियल मैड्रिड पर मुख्य रूप से रेफरी के साथ दुर्व्यवहार के कारण उसके खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए गए है। रियल मैड्रिड को सेल्टा विगो के साथ मैच के दौरान दूसरे हाफ में डिफेंडर फ्रान गार्सिया और अल्वारो कैरेरास और फॉरवर्ड एंड्रिक को दिखाए गए रेड काडर् के लिए भारी अनुशासनात्मक कीमत चुकानी पड़ी। गार्सिया पर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन की अनुशासनात्मक कमेटी ने एक मैच का बैन लगाया है, जिसे वह इस वीकेंड डेपोर्टिवो अलावेस के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकेंगे। उन्हें दो येलो काडर् मिलने के बाद मैच से बाहर कर दिया गया था। हालांकि, कैरेरास और एंड्रिक को दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, कैरेरास को रेफरी क्विंटरो गोंजालेज को बाहर किए जाने के बाद'एरेस मालिसिमो'(तुम बहुत बुरे हो) कहने के लिए सजा दी गई है।

मैदान पर नहीं उतरने वाले एंड्रिक को भी रेड काडर् दिखाया गया और'बेंच से उठकर टेक्निकल एरिया से बाहर जाने, चौथे रेफरी पर चिल्लाने और टेक्निकल स्टाफ के सदस्यों द्वारा रोके जाने की जरूरत पड़ने'के लिए दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया। घुटने की सर्जरी के बाद फिलहाल बाहर चल रहे डैनी कार्वाजल को भी मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के टनल में रेफरी का अपमान करने के लिए दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 विश्व कप टीम की घोषणा की, दो भारतीयों को मिली जगह

मेलबर्न **(एजेंसी)**। नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले पुरुषों के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम में भारतीय मूल के दो खिलाड़ियों आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स को शामिल किया गया है। आर्यन उपयोगी बल्लेबाज और धीमी गति के बाएं हाथ के स्पिनर हैं जबकि जेम्स ऑलराउंडर हैं जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं। यह दोनों उस टीम का हिस्सा थे जो सितंबर में युवा टेस्ट और वनडे श्रृंखला में भारत के खिलाफ खेली थी।

भारतीय मूल के क्रिकेटरों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम में श्रीलंकाई मूल के दो खिलाड़ी (नादेन कूरे और नितेश सैमुअल) और चीनी मूल का एक खिलाड़ी (एलेक्स ली यंग) भी शामिल हैं। ओलिवर पीक टीम के कप्तान हैं।

ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम के मुख्य कोच टिम नीलसन ने कहा, 'आईसीसी अंडर19 विश्व कप के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारा ध्यान ऐसे खिलाड़ियों के चयन पर रहा है जिनके कौशल एक-दूसरे के पूरक हों और जिनसे हम टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उन्होंने सितंबर में भारत के खिलाफ अंडर19 श्रृंखला और हाल ही में पर्थ में खोली गई राष्ट्रीय अंडर19 चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था।' ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में आयरलैंड, जापान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। टीम जनवरी की शुरुआत में नामीबिया पहुंचेगी और नौ से 14 जनवरी तक अभ्यास मैच खेलेगी।

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 पुरुष टीम : ओलिवर पीक, कैसी बार्टन, नादेन कूरे, जेडन ड्रेपर, बेन गॉर्डन, स्टीवन होगन, थॉमस होगन, जॉन जेम्स, चार्ल्स लाचमंड, विल मलाजचुक, नितेश सैमुअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विलियम टेलर, एलेक्स ली यंग।

फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं आरजे महवश
एक्टर जितेंद्र कुमार के साथ करेंगी रोमांस

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड और पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवश अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' की आज ऑफिशियली ऐलान हो गई है। इस फिल्म को कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूज़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस फिल्म के ऐलान के साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए की गई है, जिसे रेमो डिसूजा ने शेयर किया है। वहीं महवश के साथ इस फिल्म में एक्टर जितेंद्र कुमार हैं। वहीं इस वीडियो में जितेंद्र कुमार की आवाज में वॉइस ओवर है।

इस फिल्म में जितेंद्र कुमार गुलाब हकीम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, आरजे महवश उनके ऑपोजिट नगमा का किरदार निभाकर अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। अनाउंसमेंट वीडियो में महवश की कोई झलक नहीं दिखाई गई है, जबकि जितेंद्र कुमार सिर्फ एक तस्वीर में नाजर आए हैं। इस वीडियो में जितेंद्र कुमार गुलाब और नगमा की 'अनोखी मोहब्बत' का परिचय देते हैं। रेमो डिसूजा ने वीडियो शेयर करते हुए फिल्म की कहानी का सार कैप्शन में बताया। उन्होंने लिखा, 'गुलाब और नगमा की मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जान कम है, लेकिन जुनून ज्यादा है।' रेमो ने बताया कि गुलाब में मोहब्बत का कीड़ा है, जबकि नगमा में एक 'कुदरत' का आकर्षण है। यह प्रेम कहानी जिद और 'दिल धड़कने' के इर्द-गिर्द घूमती है। 'टेढ़ी है पर मेरी है' एक रोमांटिक-कॉमेडी बताई जा रही है, जिससे 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार दर्शकों को हंसाते और रोमांस करते दिखेंगे। रेमो डिसूज़ा द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान ने किया है। इस फिल्म में म्यूजिक नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार इस्माइल दरबार ने गया है।

'मेरे कपड़े वापस नहीं किए...', तान्या मित्तल पर लगा गंदा इल्जाम, अमीरी और इज्जत का उड़ रहा मजाक

'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, जो पूरे शो के दौरान अपनी अमीरी के को लेकर चर्चा में रही थीं। लेकिन अब तान्या एक और विवाद में फंस गई हैं। शो के अंदर उनकी 'रिच गर्ल' वाली इमेज पर अक्सर घरवाले और सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठाते रहे थे, और अब एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट ने उन पर धोखाधड़ी और खराब व्यवहार का आरोप लगाया। तान्या मित्तल पहले नीलम गिरी को अनफॉलो करने की वजह से सुर्खियों में आईं और अब तान्या मित्तल पर उनके स्टाइलिस्ट ने कपड़े वापस न करने, पेमेंट क्लियर न करने और इंडस्ट्री के लोगों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है।

स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर तान्या मित्तल के व्यवहार पर कड़ा एतराज़ जताया है। रिद्धिमा ने आरोप लगाया कि उन्होंने शो के दौरान और बाहर भी तान्या का लगातार साथ दें रहीं थीं। रिद्धिमा ने लिखा, 'मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में तान्या को सपोर्ट किया है। आप मेरे सभी इंटरव्यू, मैंने जो बाइट्स रिकॉर्ड किए हैं, सेलिब्रिटी वोटिंग वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो देख सकते हैं। यहां तक कि उनके अपने इंटरव्यू में भी मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी। मेरे से ही कपड़े सोर्स करवाकर हमें ही एटीट्यूड दिखा रही हैं।'

रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि तान्या मित्तल पर उनके महंगे डिजाइनर कपड़ों को वापस नहीं किया है। उन्होंने स्टाइलिस्ट और डिजाइनर के बीच का अंतर बताते हुए कहा कि उन्होंने तान्या को पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी और लहंगा भेजा था। रिद्धिमा ने आगे लिखा, 'पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी और लहंगा मैंने भेजा था और वे सभी महंगे थे। लेकिन, अब तक कुछ भी वापस नहीं किया गया है।' रिद्धिमा ने यह भी कहा कि तान्या को कपड़े पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी तारीफ नहीं की। उन्होंने अंतिम में लिखा कि 'ऐसी होती है क्या इज्जत'।

भारतीय उत्पादों पर मैक्सिको का सख्त वार, लगाया 50 फीसदी टैरिफ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मैक्सिको की सीनेट ने बुधवार को भारतीय उत्पादों सहित कई एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर अधिकतम 50इ तक शुल्क लगाने की मंजूरी दे दी है। इस नए निर्णय के दायरे में भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। यह शुल्क उन सभी देशों पर लागू होगा जिनके साथ मैक्सिको की कोई औपचारिक व्यापारिक संधि मौजूद नहीं है। घरेलू व्यापार समूहों और कई सरकारों के कड़े विरोध के बावजूद पारित यह कदम हाल के वर्षों में मैक्सिको की सबसे सख्त व्यापार नीतियों में गिना जा रहा है। नए नियमों के तहत 2026 से ऑटो, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील जैसे उत्पादों पर 50इ तक टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अधिकांश अन्य सामानों पर 35इ तक शुल्क तय किया गया है। यह प्रस्ताव सीनेट में 76 मतों से पास हुआ, जबकि पांच सदस्यों ने इसका विरोध किया और 35 सदस्य मतदान से दूर रहे। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती मसौदे में लगभग 1, 400 उत्पादों पर भारी शुल्क का प्रावधान था लेकिन संशोधित ड्राफ्ट में लगभग दो-तिहाई कैटेगरी में टैक्स कम किया गया। सरकार का कहना है कि यह नीति आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से मैक्सिको को दो प्रमुख लाभ होंगे। पहला, अमेरिका के साथ उसके संबंध मजबूत होंगे, खासकर तब जब यूएसएमसीए की समीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। दूसरा, सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिससे बजट घाटा कम करने में मदद की उम्मीद है। अनुमान है कि इस नीति से मैक्सिको को अगले वर्ष लगभग 3.76 बिलियन डॉलर की कमाई हो सकती है। नीति के समर्थक दलों का तर्क है कि सस्ते एशियाई उत्पादों ने कई वर्षों से मैक्सिको की स्थानीय इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ाया है, और घरेलू उत्पादन को बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। विपक्षी पार्टी ईं के नेता मारियो वाजकेज़ ने कहा कि अंत में इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह कमजोर उद्योगों को राहत दे सकता है। उनका कहना था कि यह नीति चीन जैसे देशों के कम दाम वाले उत्पादों की प्रतिस्पर्धा से स्थानीय व्यवसायों को बचाती है और रोजगार संरक्षण में सहायक हो सकती है। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि वह स्पष्ट करे कि इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैसे किया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सके।

सत्ता पक्ष की मोरेना पार्टी ने इस नीति का और भी दृढ़ समर्थन किया। सीनेट की आर्थिक समिति के प्रमुख इमैनुएल रेयेस ने कहा कि नए शुल्क मैक्सिको की वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिति को मजबूत करेंगे और प्रमुख उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि जनता के हित में देश की आर्थिक दिशा तय करने का प्रयास है।

भारत और मैक्सिको के बीच बढ़ता व्यापार भी इस निर्णय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.71 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 8.98 अरब डॉलर और मैक्सिको से आयात 2.73 अरब डॉलर था, जिससे भारत को 6.25 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला। भारत के प्रमुख निर्यातों में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स सबसे ऊपर रहे, जिनका मूल्य लगभग 1.99 अरब डॉलर था।

2026 में शेयर बाजार में जोरदार तेजी की भविष्यवाणी, निफ्टी जाएगा 32, 000 पार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कोटक सिक्योरिटीज ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि निफ्टी 2026 के अंत तक 24इ तक उछलकर 32, 000 के स्तर को पार कर सकता है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब 2025 में बाजार सीमित दायरे में फंसा रहा और रिटर्न बेहद मामूली रहे। कोटक की 'मार्केट आउटलुक 2026' रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12-15 महीनों में भारतीय शेयर बाज़ार लगभग फ्लैट रहा और निफ्टी ने कोई खास तेजी नहीं दिखाई। कोटक का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में कंपनियों के मुनाफे में तेज उछाल देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 में निफ्टी 50 कंपनियों का नेट प्रॉफिट 6.6 प्रतिशत बढ़ा था ।

पश्चिम रेलवे

मटेरियल मैनेजमेंट विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर सूचना संख्याः एस/72/2025 दिनांक 08.12.2025

अ. क्र.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
759	पी एंड सी हेतु पृथक स्लीपरः वस्तु (A): कैंची क्रॉसओवर का भाग – आरडीएसओ प्रलेख संख्या टी-8109 के अनुसार। वस्तु (B): 1 in 8.5 एकल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग – आरडीएसओ प्रलेख संख्या टी-6493 के अनुसार। वस्तु (C): आरडीएसओ प्रलेख संख्या टी-6494 के अनुसार 1 in 8.5 द्वि-स्लिप (डबल स्लिप) डायमंड क्रॉसिंग।	2906.72 Mtr	31-Dec-25
760	मोटर सस्पेंशन यूनिट के लिए टेपर्ड रोलर बेयरिंग का सेट	480 Set	31-Dec-25
761	66 KV (E) ग्रेड सिंगल कोर 400 sq.mm	5000 Mtr	31-Dec-25
762	हिताची TM के लिए सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग का सेट	348 Set	01-Jan-26
763	इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, 220mm	487 Nos	05-Jan-26
764	Wap5 लोको के लिए हर्थ कपलिंग स्टार का सेट	14 Set	06-Jan-26
765	LHB कोचों के अर्थिंग उपकरण के लिए मेंटेनेंस किट सेट नंबर 01, किट में 03 आइटम शामिल हैं	1687 Set	06-Jan-26
766	एंड शील्ड	17 Nos	09-Jan-26
767	UIC टाइप रबर वेस्टिब्यूल व्यवस्था	110 Nos	20-Jan-26
768	E-70 ब्रेक कंट्रोल सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स का सेट	1 Set	21-Jan-26

ईएमडी, खरीद प्रतिबंधों और विस्तृत टेंडर शर्तों के बारे में विस्तृत नोटिस के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 0878

Like us on: facebook.com/WesternRly | Follow us on: X.com/WesternRly

मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

डिविजनल रेलवे मैनेजर (S&T), पहली मंज़िल, पार्सल ऑफिस बिल्डिंग, P.F. No. 14 & 15 के ऊपर, सेंट्रल रेलवे, मुंबई CST 400 001, भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रतिष्ठित ठेकेदारों से एकल निविदा के लिए आमंत्रित किया गया है। **निविदा सूचना नं. सीआर/बीबी/सं.एवंदु.सं/पूर्व 2025/52. कार्य का नाम:** मुंबई डिवीजन के नवशेवा, उरण और रंजनपद (शेमातिखार) स्टेशनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम (एम / एस हिताची रेल एसटीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का तीन साल के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध । **लगभग मूल्य:** Rs. 77.00/- लाख. **खुलने की तारीख:** 02.01.2026. **ईएमडी:** 1,54,000/-. **वैधता:** 60 दिन. **समापन अवधी:** 36 महीने. यह निविदा 15/06/2017 दिनांकित सार्वजनिक खरीद नीति (भारत में बनाओ) आदेश 2017 का अनुपालन करती है। निविदाओं का पूरा व्यौरा मध्य रेलवे में उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पूरी निविदा दस्तावेजों को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाओं का पूरा विवरण मंडल रेल प्रबंधक (एस एंड टी) के कार्यालय, मुंबई सीएसटी के "नोटिस बोर्ड" में भी उपलब्ध है ।

म.रे.प्र.(सं. एवंदु.सं.)
छ. शि. ट. मुंबई

APEX-705

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

इंजिनियरींग कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) सोलापुर, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-निविदाये आमंत्रित करते है। **निविदा क्र.:** 19-2025-SrDENCo **कार्य का नाम:** Provision of Stabling and supporting work like Portal, Shotcreting, Rock Bolting etc. at critical locations inside Tunnel No.2 in KWV-LUR section in Solapur Division. **अनुमानित लागत:** Rs.14,24,83,741.00 **बयाना राशि:** Rs. 8,62,400.00 **समापन की अवधी:** 12 Months **अनुरक्षण की अवधी:** 12 Months **www.ireps.gov.in इस वेबसाईट पर टेंडर अपलोड करणे कि अंतिम दिनांक और समय:** 25/12/2025 को 15.00 बजे तक **www.ireps.gov.in इस वेबसाईट पर टेंडर खुलने का दिनांक और समय:** 25/12/2025 को 15.30 बजे तक * निविदाकारोंसे निवेदन हैं की कोड़ बदलाव/ शुध्दिपत्र (यदि हो) के लिये Website: **www.ireps.gov.in** पर टेंडर बंद होने की तारीख तक समय समय पर भेंट दे।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य)
मध्य रेल सोलापूर

Apex-086

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

आईआरसीटीसी द्वारा चुनिंदा वंदे भारत / अमृत भारत ट्रेनों में प्रतिष्ठित फूड एवं बेवरेज ऑपरेटरों के माध्यम से 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC)' भोजन परीक्षण

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। आईआरसीटीसी वर्तमान में भारतीय रेल के नेटवर्क पर प्रतिदिन लगभग 16.50 लाख भोजन परोस रहा है और यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ट्रेनों में भोजन सेवाओं की गुणवत्ता में 'मौलिक परिवर्तन' लाने तथा ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं में स्पष्ट सुधार लाने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी ने कुछ चुनिंदा ट्रेनों में भोजन परीक्षण प्रारम्भ किए हैं। इन परीक्षणों का मुख्य फोकस पूरी आपूर्ति श्रृंखला में रसोई परिवेश, भोजन उत्पादन प्रक्रिया, भोजन ट्रांसफर और भोजन सेवा पर है।

इस दिशा में आईआरसीटीसी खाना बनाने और सर्व करने की प्रक्रिया को अलग करते हुए इदण चला रहा है, ताकि प्रतिष्ठित ब्रांडेड F&B प्लेयर्स–जैसे इंडस्ट्रियल किचन, रेस्तरां चेन और फ्लाइट कैटरर्स–को यात्रियों को ताज़ा, स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया जा सके। यह इदण विभिन्न जोन्स में नवनिर्मित वंदे भारत एवं अमृत भारत ट्रेनों में संचालित किया जा रहा है।

इस इदण के अंतर्गत चयनित ट्रेनों की सूची निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 20101/20102 - नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेसः M/s Haldiram's (Nagpur) तथा Elior (Secunderabad)

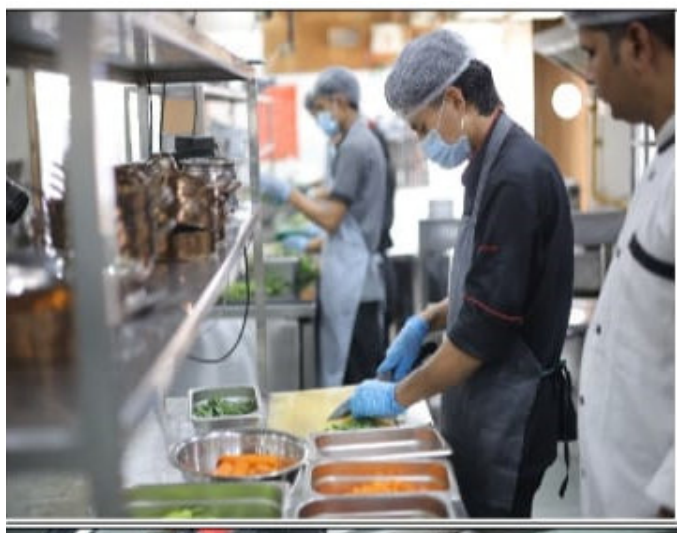

ट्रेन संख्या 14047/14048 - दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारतः M/s Touch Stone Foundation (Delhi)

ट्रेन संख्या 20633/20634 - कासरगोड-त्रिवेंद्रमः Casino Air Caterers & Flight Services (CAFS)

ाथा ट्रेन संख्या 20631/20632 - मंगलुरु-त्रिवेंद्रम वंदे भारत (16/12/25 से प्रारंभ) - CAFS

ट्रेन संख्या 26901/26902 - अहमदाबाद-वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेसः M/s CAFS Kitchen (Gandhinagar) एवं M/s Safal Foodies (Rajkot)

ट्रेन संख्या 26401/02 एवं ट्रेन संख्या 26403/04 - श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनेंः Vaishno Devi Sarovar Portico (Katra & Srinagar)

ट्रेन संख्या 15567/15568 - बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेसः M/s ISKON, Dwarka

इन भोजन परीक्षणों के माध्यम से यात्रियों को विविध, रेस्तराँ-स्तरीय मेन्यू उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन भी शामिल हैं, ताकि यात्रा के दौरान संतुष्टि स्तर में वृद्धि हो। उपरोक्त ट्रेनों में भोजन सेवाओं को लेकर यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस PoC से प्राप्त अनुभवों का विश्लेषण कर आईआरसीटीसी भविष्य में कैटरिंग सेवाओं में और अधिक सुधार एवं विस्तार लाने की दिशा में काम करेगा, ताकि हमारे मूल्यवान यात्रियों को और भी बेहतर सेवाएँ मिल सकें।

अरुणाचल हादसाः 22 मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 18 शव बरामद, एक ही गांव के रहने वाले थे सभी श्रमिक

ईटानगर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के चगलागाम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। बता दें कि बुधवार को हायुलियांग-चगलागाम सड़क पर किलोमीटर 40 के पास एक वाहन दुर्घटना की जानकारी मिली थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, जो किसी तरह चिप्रा जीआरईएफ कैंप तक पहुंच पाया, ने बताया कि 8 दिसंबर की रात 22 मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिर गया था। दुर्घटना स्थल चगलागाम से लगभग 12 किलोमीटर पहले अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है, जहां सीमित संपर्क होने के कारण स्थानीय एजेंसियों, ठेकेदारों या किसी नागरिक प्रतिनिधि द्वारा घटना की सूचना नहीं दी जा सकी।

अब तक 18 मजदूरों का शव मिला

गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस रावत ने बताया कि गुरुवार को स्पीयर कोर ने कई सर्च और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल दल, जीआरईएफ प्रतिनिधि, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एडीसी हायुलियांग को मौके पर रवाना किया। करीब चार घंटे की तलाशी और रस्सी के सहारे नीचे उतरने के बाद 11:55 बजे ट्रक को सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे घने जंगल और पत्तियों की वजह से अत्यंत कठिनाई से देखा जा सका। अब तक 18 शव दिखाई दिए हैं और उन्हें बेल-रोप तकनीक से निकाला जा रहा है। इनमें से 19 की पहचान हो चुकी है। 17 शव निकाले जा चुके हैं। ये सभी तिनसुकिया जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे और अरुणाचल में एक हॉस्टल के निर्माण कार्य के लिए गए थे।

जानकारी के अनुसार, डंपर ट्रक मजदूरों को अरुणाचल प्रदेश के एक निर्माण स्थल पर ले जा रहा था। यह सभी तिनसुकिया के गेलापुखुरी टी एस्टेट से थे। इनमें शामिल हैंः बुधेस्वर दीप, राहुल कुमार, समीर दीप, जून कुमार, पंकज मांकी, अजय मांकी, विजय कुमार, अभय भूमिज, रोहित मांकी, बीरेन्द्र कुमार, अगर तांती, धीरन चेटिया, रजनी नाग, दीप ग्वाला, रामचाबक सोनार, सोनाटन नाग, संजय कुमार, करण कुमार और जोनास मुंडा।

खोज व बचाव अभियान जारी

डिप्टी कमिश्नर स्वप्निल पॉल ने बताया, लगभग 11 बजे सूचना मिली कि अंजॉ जिले में एक वाहन खाई में गिर गया है। इसके बाद हमने अंजॉ और तेजू के डीसी से संपर्क किया। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और खराब दृश्यता के बावजूद सेना, सिविल प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां मिलकर शेष लोगों की तलाश और त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं।

2019 रामलिंगम हत्याकांड, एनआईए ने 5 आरोपियों में से 2 को किया गिरफ्तार

2019 के रामलिंगम हत्याकांड में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने तमिलनाडु में रची गई इस क्रूर हत्या में शामिल दो फरार घोषित अपराधियों और हमलावरों के तीन अन्य पनाहदाताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के निवासी मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद नबील हसन के रूप में पहचाने गए ये घोषित अपराधी रामलिंगम की हत्या के बाद से लगभग सात वर्षों तक फरार थे।

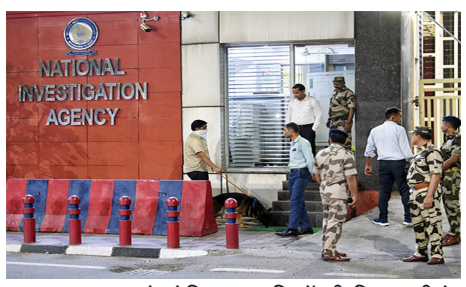

5 फरवरी, 2019 को तमिलनाडु के तंजावुर शहर में रामलिंगम की कथित तौर पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

एनआईए ने बताया कि सहयोगी एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर दो घोषित आरोपियों को वेल्लोर जिले के पल्लिकोंडा में पकड़ा गया। एनआईए ने एक बयान में कहा, 'तंजावुर जिले के पीएफआई सदस्य, इन दोनों ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर रामलिंगम की हत्या की साजिश रची और उनके हाथ काट दिए। आज तक, घोषित अपराधियों में से पांच को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना अभी भी फरार है।

दो घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद, एनआईए ने बताया कि उसने इस मामले में शामिल तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। चेन्नई जिले के निवासी के मोहिदीन, मोहम्मद इमरान और थमीम अंसारी हत्या के बाद फरार आरोपियों को छिपाने और उनके आने-जाने में मदद करने के दोषी पाए गए। एनआईए ने 7 मार्च, 2019 को तिरुविदैमरुथुर पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया और अगस्त 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया।

एमएसईटीसीएल और इसरो-एनआरएससी के बीच वेब-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के फेज-2 विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL), ऊर्जा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (एनआरएससी) के बीच वेब-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System – DSS) के फेज-2 विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रणाली राज्य के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना एवं निगरानी को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी।

यह पहल एमएसईटीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में कंपनी की डिजिटल एवं भू-स्थानिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू पर एमएसईटीसीएल की ओर से श्री सतीश चव्हाण, निदेशक (ऑपरेशंस) द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रमों को दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

हस्ताक्षर समारोह हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया–कुछ प्रत्यक्ष रूप से नागपुर स्थित रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर-सेंट्रल में तथा शेष वर्चुअल माध्यम से। एनआरएससी की ओर से उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे–

डॉ. प्रकाश चौहान, निदेशक, एनआरएससी

डॉ. एस. के. श्रीवास्तव, सीजीएम (रीजनल सेंटर्स), एनआरएससी

डॉ. जी. श्रीनिवासन, जनरल मैनेजर, RRSC-C

एमएसईटीसीएल की ओर से उपस्थित रहे–

सतीश चव्हाण, निदेशक (ऑपरेशंस)

प्रमोद चिमणकर, मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ)

विशाल वाघचौरे, अधीक्षण अभियंता (विशेष परियोजनाएँ)

एमएसईटीसीएल और एनआरएससी-इसरो के बीच सहयोग वर्ष 2017 में फेज-1 से प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत एमएसईटीसीएल के पहले वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म का विकास किया गया। इस परियोजना में लगभग 94,000 ट्रांसमिशन टावरों, उपकेंद्रों और ईएचवी लाइनों का भू-स्थानिक डेटा इसरो के भुवन प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक दर्ज किया गया।

फेज-1 में सर्किट-वार मैपिंग, रों कॉरिडोर विज़ुअलाइज़ेशन, विश्लेषणात्मक उपकरण, तथा ईआरपी आधारित एमआईएस डैशबोर्ड जैसी विशेषताओं को भी शामिल किया गया। इस चरण ने एमएसईटीसीएल की आंतरिक जीआईएस क्षमता को मजबूत करते हुए पीएम गतिशक्ति जैसी राष्ट्रीय पहलों में प्रभावी योगदान सुनिश्चित किया।

फेज-2 के प्रमुख उद्देश्य

नए एमओयू के साथ फेज-2 के तहत एक उन्नत डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें निम्न क्षमताएँ शामिल होंगी–

ट्रांसमिशन कॉरिडोर की योजना एवं उपकेंद्र स्थल मूल्यांकन

भू-स्थानिक प्रभाव विश्लेषण

निर्माण कार्य की रियल-टाइम प्रगति निगरानी

परिचालन डेटा (फाल्ट, वोल्टेज प्रोफाइल, ऊर्जा प्रवाह, आर एंड एम व्यय) का समाकलन

मोबाइल एवं वेब आधारित जीआईएस टूल

संरचित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

फेज-2 एमएसईटीसीएल को केवल एसेट मैपिंग से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान निर्णय समर्थन की दिशा में ले जाता है, जिससे योजना दक्षता और संचालन संबंधी अंतर्दृष्टि में उल्लेखनीय सुधार होगा।

एमएसईटीसीएल और एनआरएससी-इसरो के बीच यह दीर्घकालिक साझेदारी राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में उन्नत भू-स्थानिक तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। एमओयू पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र की ग्रिड योजना एवं निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोल्हापुर से वैभववाड़ी रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया जाए

नागपुर। महाराष्ट्र को प्राप्त 720 किलोमीटर लंबे समुद्रतट, निर्माणाधीन वधावन बंदर और समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।

विधान भवन स्थित मंत्री परिषद सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बंदरगाह विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए तथा इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। जयगढ़, आंग्रे, रेडी और विजयवाड़ा बंदरगाहों के विकास के लिए वैभववाड़ी- कोल्हापुर रेल मार्ग तैयार किया जाना आवश्यक है। इस मार्ग के निर्माण में राज्य सरकार का आर्थिक सहभाग सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वधावन बंदर से नासिक तक महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग बनाया जा रहा है। इस राजमार्ग के दोनों ओर प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास किया जाए। बंदरगाह क्षेत्रों के विकास के महत्व को देखते हुए इन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने हेतु निवेशकों आकर्षित किया जाए। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआयडीसी) और बंदरगाह विभाग के समन्वय से एक कंपनी स्थापित की जाए। साथ ही निर्माणाधीन वधावन बंदर और उससे जुड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण का गठन किया जाए।

मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस परियोजना के लिए बोटें पूरी तरह इलेक्ट्रिक आधारित हों। प्रारम्भिक चरण में हाइब्रिड मॉडल भी अपनाया जा सकता है तथा नई बोटों की खरीद की जाए। 'कोची से भी बड़ा और बेहतर मुंबई वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होना चाहिए,' ऐसा उन्होंने कहा। बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना महाराष्ट्र में वर्तमान में 36 यात्री जलमार्गों के माध्यम से प्रति वर्ष 1.80 करोड़ यात्रियों का आवागमन होता है। मुंबई महानगर क्षेत्र में 21 जलमार्ग कार्यरत हैं, जिनसे करीब 1 करोड़ 60 लाख यात्रियों की वार्षिक आवाजाही होती है। प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के तहत 21 आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे और लगभग 200 नॉटिकल माइल के मार्ग विकसित किए जाएंगे। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

भारत की समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव, तटरक्षक बल ने की जब्त; चालक दल के 11 सदस्य भी गिरफ्तार

अहमदाबाद। भारत की जल सीमा के अंदर घुसने वाली एक पाकिस्तानी नाव को तटरक्षक बल ने गुरुवार को जब्त कर लिया। इस नाव में सवार 11 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में एक पाकिस्तानी नाव को जब्त कर लिया है और उसके चालक दल के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की जांच के लिए गुजरात की जाखौ मरीन पुलिस को सौंप दिया गया है। गुजरात रक्षा पीआरओ विंग कमांडर अभिषेक कुमार तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंदर चालक दल के 11 सदस्यों वाली एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त किया।

भारत के समुद्री क्षेत्र में सतर्कता कड़ी

उन्होंने कहा कि यह पाबंदी तटरक्षक बल के निरंतर समुद्री अभियानों और भारत के समुद्री क्षेत्रों (एमजेडआई) के भीतर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मजबूत प्रवर्तन को बनाए रखते हुए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने आगे कहा, 'भारत के समुद्री क्षेत्र में निरंतर सतर्कता हमारी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीति की एक आधारशिला बनी हुई है।' आईसीजी ने भी इस पाबंदी की पुष्टि की।

गिरफ्तारी पर क्या बोला भारतीय तटरक्षक बल?

आईसीजी की ओर से एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया, 'भारतीय तटरक्षक बल ने देश के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रहे एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाले पोत और उसके चालक दल के 11 सदस्यों को रोका और गिरफ्तार किया।' इसमें कहा गया है, 'यह निर्णायक कार्रवाई भारतीय तटरक्षक बल की अटूट सतर्कता और समुद्री सीमाओं की रक्षा करने तथा मध्य समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। निरंतर निगरानी और सक्रिय अभियान हमारी समुद्री सुरक्षा रणनीति का आधार हैं।'

मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग, टीकेएस एलंगोवन ने केंद्र की भागीदारी को लेकर जताई आपत्ति

चेन्नई **(एजेंसी)**। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू किए गए महाभियोग प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कथित संलिप्तता की आलोचना करते हुए इसे 'असंवैधानिक' बताया और कहा कि यह मामला पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। एएनआई से बात करते हुए एलंगोवन ने कहा कि यह राज्य का मामला है, लेकिन केंद्र का इसमें शामिल होना असंवैधानिक है। भाजपा की ओर से न्यायाधीश का कार्य करना स्वयं कानून के विरुद्ध है। इसीलिए हमने नोटिस जारी किया है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमने यह महाभियोग विधेयक क्यों लाया है। उन्होंने अपने हमले को और तेज करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर 'हिंदू विरोधी' होने का आरोप लगाया और संगठन पर राज्य में मनु धर्म थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, बहन की शादी के लिए 14 दिनों की मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को गुरुवार को 16 से 29 दिसंबर तक 14 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई ताकि वे 27 दिसंबर को होने वाली अपनी बहन की शादी में शामिल हो सकें। जानकारी के अनुसार, उनकी याचिका पर दिल्ली के कड़कड़डूमा न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने सुनवाई की, जहां उनकी अस्थायी राहत की अपील पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी हैं और उन पर कई अन्य व्यक्तियों के साथ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और कई आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं।

न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें

दिल्ली दंगों के बाद से खालिद को गिरफ्तारी के बाद से जेल में रखा गया है। अंतरिम जमानत आदेश उनके लिए थोड़े समय की राहत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर बाहर रहेंगे। 'चूंकि शादी आवेदक की अपनी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।

शर्तों के अनुसार, खालिद इस अवधि के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से मिल सकते हैं। उन्हें या तो अपने घर पर या न्यायालय को सूचित किए गए विवाह समारोह स्थलों पर रहना होगा। यह राहत मिलने से पहले, खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत दोनों में अर्जी दी थी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)